गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधान सेवक तक की अनवरत यात्रा के 25वें वर्ष में प्रवेश पर विशेष रिपोर्ट | पेज | 06-17

वर्ष: 6 अंक: 07

1-15 अक्टूबर, 2025 (निःशुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

ई-कॉपी के लिए QR स्कैन करें

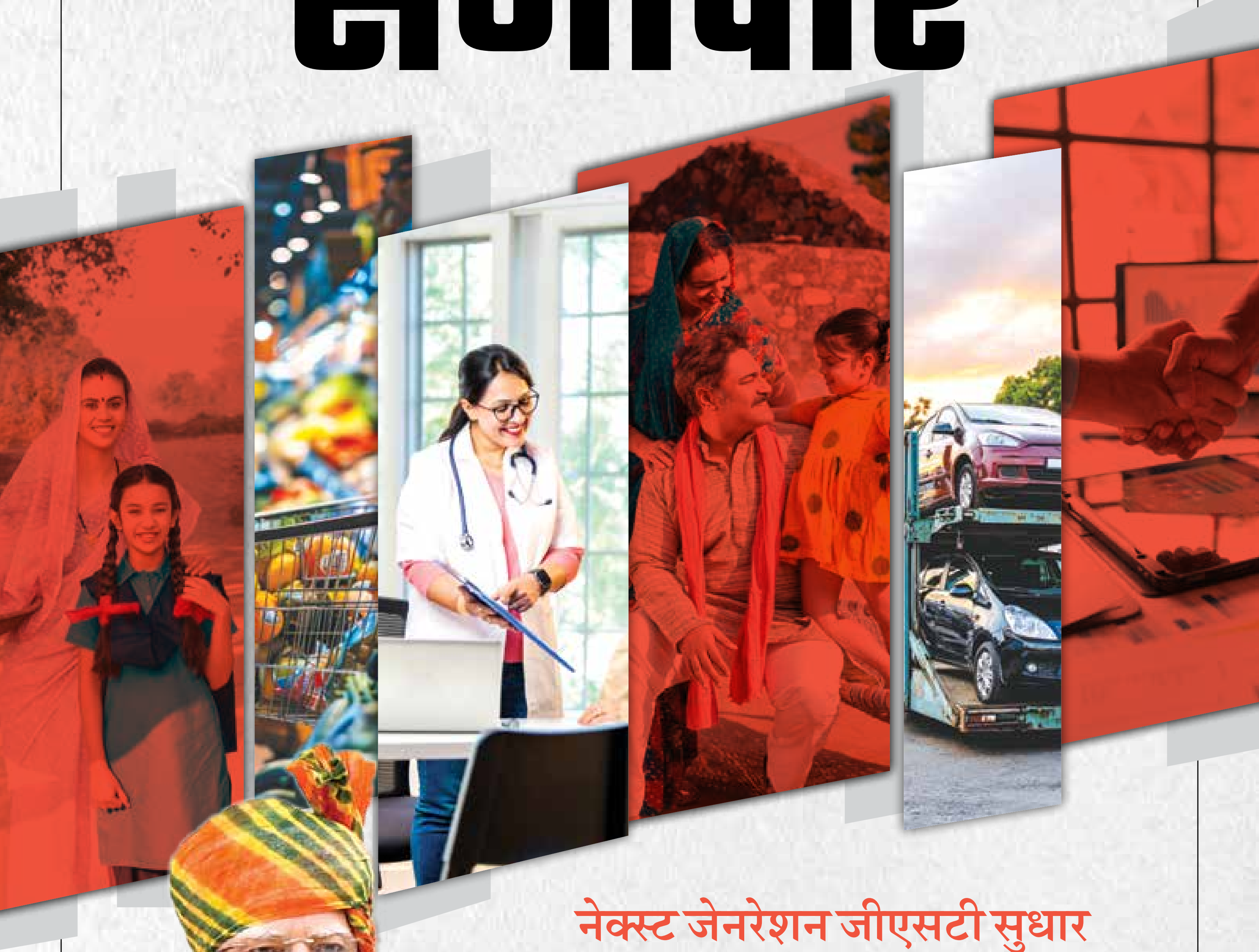

नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार

भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वर्णिम युग का आरंभ

इस 22 सितंबर से लागू ऐतिहासिक नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार से विकसित भारत के निर्माण को मिलेगी नई गति, हर परिवार होगा लाभान्वित, हर घर होगा खुशहाल...

मन की बात : 11 वर्ष की यात्रा

आह्वान बने जनांदोलन

विजयादशमी के पर्व के दिन 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुए 'मन की बात' कार्यक्रम देशवासियों की अच्छाइयों और उनकी सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। यह कार्यक्रम कोटि-कोटि भारतीयों के 'मन की बात' है। यह उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। यह एक ऐसा कार्यक्रम बन गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल की गहराइयों से लोगों तक पहुंचते हैं और उनके शब्द जन आंदोलन बन जाते हैं। इस कार्यक्रम से कई महत्वपूर्ण जन आंदोलनों की हुई है शुरूआत...

जनांदोलन 01
स्वच्छ भारत मिशन
03 अक्टूबर 2014

जनांदोलन 02
अंगदान महादान
25 अक्टूबर 2015

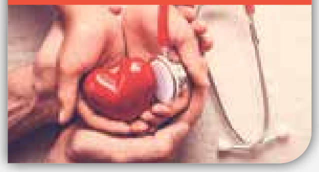

जनांदोलन 03
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
24 सितंबर 2017

जनांदोलन 04
योग दूर भगाए रोग
25 मार्च 2018

जनांदोलन 05
जल संरक्षण
28 जुलाई 2019

जनांदोलन 06
कोविड से लड़ाई
26 अप्रैल 2020

जनांदोलन 07
वोकल फॉर लोकल
24 अक्टूबर 2021

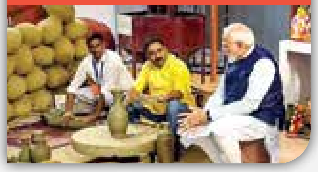

जनांदोलन 08
हर घर तिरंगा
31 जुलाई 2022

जनांदोलन 09
आजादी का अमृत महोत्सव
28 अगस्त 2022

जनांदोलन 10
एक पेड़ मां के नाम
29 सितंबर 2024

जनांदोलन 11
खाने के तेल में 10% की कमी
23 फरवरी 2025

न्यू इंडिया
समाचार

वर्ष: 6, अंक: 07 I 1-15 अक्टूबर, 2025

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

चीफ डिजाइनर
श्याम तिवारी

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

राष्ट्र का ऐतिहासिक दिवाली उपहार नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार

भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वर्णिम युग का आरंभ

आवरण कथा

परिवर्तनकारी सुधार के जरिए जीएसटी 2.0 के साथ 22 सितंबर से नए युग का आरंभ। आम नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव, उद्यमियों को सरलता और अगली पीढ़ी को सशक्त करने वाले केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से शुरू हो चुकी है भारत की विकसित होती अर्थव्यवस्था की नई कहानी... 18-31

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सुशासन के 25वें वर्ष में प्रवेश
राष्ट्रनीति और राजनीति के आदर्श
6-17

जापान से एससीओ तक...
भारत पर भरोसे का नया विस्तार

चीन में एससीओ बैठक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा | 44-51

समाचार सार | 4-5

तमिलनाडु की माटी से कर्तव्य पथ तक
भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने सी.पी. राधाकृष्णन | 32-33

भूपेन दा...भारत के रत्न
भूपेन हजारिका जन्म शताब्दी वर्ष पर पीएम मोदी का आलेख | 34-35

भागवत जी हमेशा से 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के प्रबल समर्थक रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष ब्लॉग | 36-38

स्वच्छता से निकला संपन्नता का नया मार्ग
स्वच्छ भारत मिशन के 11 वर्ष | 39-41

बिहार, झारखंड, प. बंगाल को कनेक्टिविटी में विस्तार की सौगात
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना को दी मंजूरी | 42-43

सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की धड़कन
सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन | 52-53

परमाणु ऊर्जा क्षमता होगी अगले छह वर्ष में तीन गुनी
देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता पर विशेष रिपोर्ट | 54-55

पूर्वोत्तर बन रहा विकसित भारत का संकल्प सारथी
प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर, मिजोरम और असम दौरा | 56-58

'वात्सल्यमूर्ति' निर्णायक नेता व कुशल प्रशासक
व्यक्तित्व में विजयाराजे सिंधिया की कहानी | 59

प्रकाशक और मुद्रक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो)। **मुद्रण:** जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 I **पत्राचार और ईमेल के लिए पता:** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 I **ईमेल-** response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812

संपादक की कलम से...

नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी से नए भारत का उदय

सादर नमस्कार।

यद दुरं यद दुराद्यम, यद च दुरै, व्यवस्थितम्,
तत् सर्वम् तपसा साध्यम तपोहिदुर्तिक्रमम।

चाणक्य के इस वाक्य से पूरी जीएसटी प्रक्रिया बेहद आसानी से समझ आती है। कोई वस्तु कितनी ही दूर क्यों न हो, उसका मिलना कितना ही कठिन क्यों न हो, वह पहुंच से कितनी ही बाहर क्यों न हो, कठिन तपस्या और परिश्रम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। जीएसटी ने इसे साकार करके दिखाया है। आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार-जीएसटी एक ऐसा महत्वपूर्ण कर सुधार है जिसने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ-साथ 'एक राष्ट्र-एक कर' की परिकल्पना को साकार किया लेकिन किसी भी सुधार में निरंतरता हो तो वह सदैव प्रवाहमान बना रहता है। यही कारण है अपनी यात्रा के 8 वर्ष पूरे कर 9वें वर्ष में चल रही जीएसटी ने अगली पीढ़ी के सुधार के जरिए नया आयाम जोड़ा है। जीएसटी और जीएसटी काउंसिल, संघीय ढांचे का सबसे अनुपम उदाहरण बनी है, जिसने सरकार, कारोबारियों के साथ आम लोगों को भी बहुत लाभ पहुंचाया है। अब इस लाभ के दायरे को जनता तक अधिक पहुंचाने की पहल हुई है जो नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू हो रही है।

इसी वर्ष आमजन को सुविधा, उद्यमियों को बल और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए जीएसटी में व्यापक सुधारों का आह्वान लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। केंद्र सरकार के स्पीड और स्केल का ही परिणाम है कि उस आह्वान पर तत्काल निर्णय हुआ। जीएसटी प्रणाली में किया गया सुधार देश को एक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला है जो न केवल आमजन के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि व्यापार जगत और समग्र अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा प्रदान करेगा। जीएसटी 2.0 ही हमारी इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है।

सेवा का पर्याय बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से अनवरत जारी सेवा, समर्पण की उनकी यात्रा इस 7 अक्टूबर को 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस पर एक विशेष रिपोर्ट भी हमारे इस अंक में शामिल है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन, फ्लैगशिप में स्वच्छ भारत मिशन के 11 वर्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, परमाणु ऊर्जा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान एवं चीन के दौरे सहित पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और डॉक्टर भूपेन हजारिका पर लिखे गए भावपूर्ण आलेख को भी इसमें स्थान दिया गया है।

इसके अलावा पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात के 11 वर्ष की यात्रा और बैक कवर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर-अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।

धीरेन्द्र

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

राष्ट्र से जुड़े कई पहलू शामिल जो जानकारीपूर्ण और सहेजने योग्य

हाल ही में मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ने का अवसर मिला। मुझे यह पत्रिका बहुत ही जानकारीपूर्ण और मूल्यवान लगी क्योंकि इसमें हमारे राष्ट्र से जुड़े कई पहलुओं को शामिल किया गया है। इस पत्रिका के आंकड़े और तथ्य बिल्कुल सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही इसकी भाषा समझने में आसान है।

rightfoundationjs@gmail.com

मूल्यवान प्रकाशन है न्यू इंडिया समाचार

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका में मेरी गहरी रुचि है क्योंकि यह एक मूल्यवान प्रकाशन है। इसमें देश की सरकारी नीतियों और विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी पढ़ने को मिलती है। मैं यह पत्रिका तेलुगु संस्करण में पढ़ता हूं क्योंकि मुझे राष्ट्रीय समाचार और पहलूओं से अपडेट रहने के लिए इस भाषा में लेख पढ़ने में विशेष रुचि है।

narendrabandaru5672@gmail.com

उत्कृष्टता के कारण पाठकों को विशेष पसंद

मैं सिराज, तेलंगाना का निवासी हूं। मेरे गांव में 'स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय' है। इस पुस्तकालय में प्रतिदिन बहुत से समाचार पत्र आते हैं। इसे पढ़ने के लिए कई पाठक और प्रतियोगी परीक्षार्थी आते हैं। उत्कृष्टता के कारण इस पुस्तकालय में 'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका को पाठक विशेष पसंद करते हैं। यह नियमित रूप से पुस्तकालय को मिलती रहे यह अनुरोध है।

md.siraj1797@gmail.com

हर अंक में मिलती है कुछ नई जानकारी

मुझे न्यू इंडिया समाचार पत्रिका जनता के बीच प्रमाणिक जानकारी प्रसारित करने के लिए अत्यधिक ज्ञानवर्धक और प्रासंगिक लगती है। इस पत्रिका के माध्यम से देश-विदेश में होने वाली सभी घटनाओं से अवगत होता हूं। हर अंक से कुछ नया सीखने को मिलता है। पत्रिका में सभी वर्तमान घटनाक्रम और बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है।

snehasurabhi5@gmail.com

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह एक अच्छी पत्रिका

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका की प्रति मुझे मिली। पत्रिका पढ़ कर बहुत ही अच्छी लगी। यह एक संपूर्ण पत्रिका है। पत्रिका के माध्यम से मैं भारत में होने वाले विकास से अवगत हो पाता हूं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह एक अच्छी पत्रिका है। हमें इस पत्रिका के सभी अंकों का बेसब्री से इंतजार रहता है।

anuragmishrabhu@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पताः कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003.
ईमेल- response-nis@pib.gov.in

न्यू इंडिया समाचार को आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर शनिवार-रविवार को दोपहर 3:10 से 3:25 बजे तक सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

ज्ञान भारतम् मिशन... भारत की संस्कृति साहित्य और चेतना का उद्घोष

पांडुलिपि में हमारे ज्ञान के भंडार पड़े है, लेकिन उसके प्रति लंबे समय तक उदासीनता रही है। अतीत में करोड़ों पांडुलिपियां नष्ट कर दी गईं, लेकिन जो शेष हैं, वे दर्शाती हैं कि हमारे पूर्वज ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के प्रति कितने समर्पित थे। अब ज्ञान भारतम् योजना के तहत देशभर में जहां भी हस्तलिखित ग्रंथ, पांडुलिपियां और सदियों पुराने दस्तावेज हैं, उनको खोज-खोज करके संजोया जा रहा है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि उस ज्ञान की समृद्धि को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जा सके। भारत के पास वर्तमान में लगभग एक करोड़ पांडुलिपियों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। इसी वर्ष आम बजट में घोषित, ज्ञान भारतम् मिशन-पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, डॉक्यूमेंटेशन और विश्लेषण के माध्यम से समूचे विश्व को फिर से भारत की अकल्पनीय ज्ञान विरासत से जोड़ने वाला है। लगभग 483 करोड़ रुपये की लागत वाले इस मिशन पर काम चल रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक इस पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान भारतम् मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। उन्होंने पांडुलिपि के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्ञान भारतम् पोर्टल की शुरूआत भी की। दुनिया में इस समय करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर की कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री है। ज्ञान भारतम् मिशन के तहत यह प्रयास किया जा रहा है कि मानवता की ये साझी धरोहर एकजुट हो। इसकी नींव 4 मुख्य पिलर पर आधारित हैं। पहला- प्रिजर्वेशन, दूसरा- इनोवेशन, तीसरा- एडिशन और चौथा- ऐडप्टेशन। देश आज स्वदेशी की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। यह मिशन उस राष्ट्रीय भावना का विस्तार है। भारत आज अपनी विरासत को अपनी ताकत के प्रतीक में बदल रहा है और इसमें ज्ञान भारतम् मिशन भविष्य के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

देश भर में 1,600 जगह बनेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

पेंशनभोगियों के हित में केंद्र सरकार अब तक के सबसे बड़े आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इसके तहत 1-30 नवंबर तक देश भर के जिला और सब-डिविजन मुख्यालय में 1600 जगह कैंप लगाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) बनाए जाएंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इन कैंपों के जरिए 2 करोड़ डीएलसी बनाने का लक्ष्य तय किया है। कार्यक्रम के तहत अत्यंत वरिष्ठ नागरिक और अलग-अलग श्रेणी के दिव्यांग पेंशनभोगियों को डोरस्टेप सेवाएं भी दी जाएंगी। बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसके लिए अक्टूबर माह में एसएमएस, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और बैनर के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। पिछली बार ऐसे ही अभियान के तहत 1.62 करोड़ डीएलसी बनाए गए थे।

ऐतिहासिक उपलब्धि...**गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 11 वर्ष में तीन गुना हुई**

हरित ऊर्जा की दिशा में अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ते हुए देश ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 250 गीगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। यह इस क्षेत्र में बीते 11 वर्ष में करीब तीन गुना की बढ़ोतरी है। पेरिस समझौते के तहत भारत अपनी कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता का आधा हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल करने का 2030 की समय सीमा का लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही इसी साल जुलाई में पूरा कर चुका है। हरित ऊर्जा की दिशा में भारत की इसी प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था, "जितने हम विश्व के प्रति संवेदनशील हैं, प्रकृति के प्रति भी उतने ही जिम्मेदार हैं।"

गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल ऊर्जा

सौर ऊर्जा	123.13 गीगावाट
पवन ऊर्जा	52.68 गीगावाट
जल विद्युत	55.22 गीगावाट
जैव ऊर्जा	11.60 गीगावाट
परमाणु ऊर्जा	8.78 गीगावाट

जी-20 देशों में सबसे कम 2% है भारत की बेरोजगारी दर

भारत में तेज आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, पीएम मुद्रा, स्टैंडअप, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएम विश्वकर्मा, पीएलआई, पीएम स्वनिधि जैसी तमाम योजनाओं ने बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन किया है। रोजगार के बढ़ते अवसरों का ही नतीजा है कि भारत में बेरोजगारी दर 2% रह गई है। यह जी-20 में शामिल सभी देशों में सबसे कम है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट-2025' का उल्लेख करते हुए यह जानकारी दी। राष्ट्रीय करियर सेवा प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए

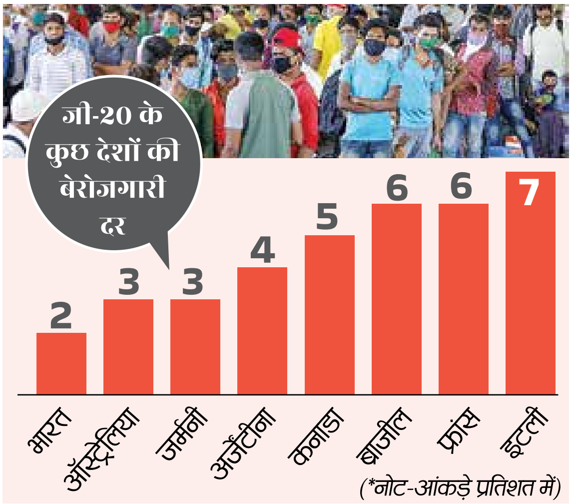

उन्होंने कहा कि लगभग 52 लाख पंजीकृत नियोक्ताओं, 5.79 करोड़ नौकरी चाहने वालों और 7.22 करोड़ से अधिक रिक्तियों के साथ यह प्लेटफार्म नौकरी लिस्टिंग प्रदान करने के साथ रोजगार संबंधी सेवाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान में पोर्टल पर 44 लाख से अधिक सक्रिय रिक्तियां हैं।

कृषि अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी... बागवानी उत्पादन में 30% वृद्धि

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो बागवानी कृषि क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। बागवानी बेहतर पोषण को बढ़ावा देती है तो कृषि में विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के साथ ही वैकल्पिक ग्रामीण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन जैसे कार्यक्रमों ने बीते एक दशक में इस क्षेत्र के कायाकल्प की नई कहानी लिखी है। इसी का नतीजा है कि पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में 30% की वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2013-14 में जहां बागवानी उत्पादन 280.70 मिलियन टन था, वहीं अगस्त, 2025 तक यह बढ़कर 367.72 मिलियन टन पहुंच चुका है। इसमें 114.51 मिलियन टन फल, 219.67 मिलियन टन सब्जी और अन्य बागवानी फसलों से 33.54 मिलियन टन उत्पादन शामिल है। बागवानी क्षेत्र की उत्पादकता के स्तर में भी सुधार हुआ।

यूं बढ़ा फल और सब्जी उत्पादन

फल उत्पादन
(लगभग 30% की वृद्धि)

2014-15	866
2023-24	1,129.7

सब्जी उत्पादन
(लगभग 22% वृद्धि)

2014-15	1,694.7
2023-24	2,072

नोटः आंकड़े लाख मीट्रिक टन में।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सुशासन के 25वें वर्ष में प्रवेश

राष्ट्रनीति

और राजनीति के आदर्श

पांच दशक से अधिक का सार्वजनिक जीवन और 25 वर्ष के शासन में 'सेवक' बनकर अपनी निष्ठा और राष्ट्र-समाज को नई दिशा देने की दृढ़ इच्छाशक्ति ही किसी नेतृत्वकर्ता को जन-जन का सम्मान दिलाती है। ऐसे ही व्यक्तित्व के तौर पर नए भारत की पहचान बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा यात्रा पर्याय है उनके व्यक्तित्व की, साहसिक निर्णय की, राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ भारत को विकसित बनाने की। जिनके बारे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं, "जब एक व्यक्ति अपने परिवार को भुलाकर, जीवन का क्षण-क्षण और शरीर का कण-कण 140 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित करता है, तभी नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति बनता है।" गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को शपथ ली थी, तब से अनवरत जारी सेवा, समर्पण की उनकी यात्रा इस वर्ष 25वें साल में प्रवेश कर रही है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट...

वह एक कर्मठ कार्यकर्ता की भांति मेहनत करते हैं, एक स्टेटसमैन की भांति देश का गौरव बढ़ाते हैं, एक टीम लीडर की भांति पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, भावुक राजनेता की भांति संवेदनशील निर्णय लेते हैं, निडर सेनापति की भांति राष्ट्ररक्षा में अडिग चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। दीपक की लौ की तरह उर्ध्व दिशा में ही सोचते हैं। राष्ट्र की सेवा यात्रा में इस पड़ाव तक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक जीवन की यात्रा में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन वे ठहरे नहीं। इसका कारण है कि उन्होंने राजनीति का पाठ भी राष्ट्रनीति की भाषा में पढ़कर उसे अपने जीवन का संस्कार बनाया और सर्वसमावेशी विकास की नई पटकथा तैयार की। न थमना, न थकना, न रुकना, अथक परिश्रम से आगे बढ़ते जाना। नए-नए लक्ष्य निर्धारित करना और अंतिम छोर तक उसे पहुंचाकर विकास की सशक्त गौरवगाथा लिखना। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की अलग पहचान है, जिनका खुद का परिवार आज भी समान्य जीवन जी रहा है क्योंकि उनके लिए 140 करोड़ से अधिक देशवासी ही उनका परिवार है।

प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, "मुझे कड़ी मेहनत से कभी थकान नहीं होती बल्कि मेहनत से गरीब जनता के चेहरे पर आई मुस्कान अत्यंत संतोष की अनुभूति करवाती है।" प्रधानमंत्री मोदी एक अतिसंवेदनशील व्यक्ति है जिनके मन में देश के दलित, गरीब, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए अपार संवेदनशीलता है और हर निर्णय करते समय हमेशा अंत्योदय और गरीब कल्याण के लिए सबसे पहले सोचना उनकी प्रकृति बन गई है।

राष्ट्रवाद को प्रेरणा, अंत्योदय को दर्शन और सुशासन की शक्ति से देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाना नए भारत का मंत्र है। निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रखने की सोच के साथ पहली बार किसी केंद्र सरकार ने समयबद्ध तरीके से अंतिम छोर तक विकास की पहुंच सुनिश्चित कर विकसित भारत की बुनियाद रख दी है।

अगर किसी को प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष की शासन यात्रा को समझना है तो इससे पहले के 30 वर्षों की कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और समाजसेवक के रूप में उनकी यात्रा को देखना और समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने 30 वर्षों तक गुजरात और देश के हर भाग का भ्रमण किया, समाज की समस्याओं को समझा और उनके समाधान पर चिंतन किया। व्यक्तियों को परखने का भी काम किया और आपदा को अवसर में बदलने का गुण भी सीखा। प्रधानमंत्री मोदी एक आदर्शवादी नेता की छवि रखते हैं, वह लक्ष्य, देश, उसके गौरव और भले के सिवा किसी की चिंता नहीं करते। उनका सबसे बड़ा योगदान देश में लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करना है। वे एक ऐसे दूरदर्शी नेता हैं जो कभी

बड़े फैसले लेना ही नहीं उसे परिणति तक पहुंचाना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का पर्याय बन चुका है। आजाद भारत में 17 सितंबर 1950 को एक गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी ने चायवाले से लेकर देश के प्रधान सेवक तक का सफर तय किया तो उनका सेवा का संकल्प ही 'नए भारत' का मंत्र बन गया है।

टुकड़ों में नहीं सोचते बल्कि पूर्णता में सोचते हैं, दूर की सोचते हैं और जो सोचते हैं उसे पूरा करते हैं। पीएम मोदी ने तुष्टिकरण की राजनीति को भी समाप्त कर दिया, आज देश के करोड़ों गरीबों के लिए बनी योजनाओं में कोई आरोप नहीं लगा सकता कि इसके लाभार्थियों में कोई भेदभाव किया गया है, सबको एक समान लाभ मिला है। सुरक्षा के नाम पर उनके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर करके दंडित करने का हौसला आज भारत के पास है। पीएम मोदी जो भी योजना लाते हैं उसमें जनभागीदारी का तत्व बहुत बड़ा होता है। जनभागीदारी के कारण ही उनको इतनी सफलता मिली है। पूरा देश यह मानता था कि जब तक अनुच्छेद 370 है तब तक कश्मीर का भारत के साथ स्थायी जुड़ाव नहीं हो सकता। 5 अगस्त 2019 की सुबह फैसला हुआ और उनके नेतृत्व में अनुच्छेद 370 और 35ए को निष्प्रभावी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव को जन जन का महोत्सव बनाया।

दरअसल, बड़े फैसले लेना ही नहीं उसे परिणति तक पहुंचाना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का पर्याय बन चुका है। आजाद भारत में 17 सितंबर 1950 को एक गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी ने चायवाले से लेकर देश के प्रधान सेवक तक का सफर तय किया तो उनका सेवा का संकल्प ही 'नए भारत' का मंत्र बन गया है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारिवारिक पृष्ठभूमि से वाकिफ है कि कैसे समाज के कमजोर तबके से निकले पीएम मोदी को दो वक्त का भोजन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वडनगर के लगभग 40×12 फुट के आकार के घर में बचपन गुजारने वाले पीएम मोदी के पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। प्रारंभिक वर्षों में पीएम मोदी भी इस चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बंटाते थे। शुरुआती वर्ष के संघर्षों ने पीएम मोदी के मन पर एक मजबूत छाप छोड़ी। जीवन के आगे के चरणों में स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उन्हें अध्यात्म की ओर ले जाना शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में भी राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। दरअसल वे उस विचार परिवार में पले-बढ़े हैं, जिसका संस्कार ही ऐसा है, जहां राजनीति और राष्ट्रनीति में से किसी एक को स्वीकार करने की जरूरत पड़े तो राष्ट्रनीति को सबसे पहले और राजनीति को दूसरे नंबर पर रखना सिखाया जाता है।

यही गुण राजनीति और व्यक्तित्व के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं, दुनिया के अन्य नेताओं से अलग करती है। उनकी जीवन यात्रा में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि की उनकी सोच ने उन्हें सदैव संबल दिया। अक्टूबर 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विकास का अलग मॉडल बनाने की दिशा में काम शुरू किया, जिसके लिए खास तौर से स्कूली शिक्षा पर फोकस किया। कुछ ऐसे पल भी आए जब विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया लेकिन पीएम मोदी इन तीक्ष्ण हमलों से कमजोर नहीं पड़े, बल्कि मजबूती के साथ काम करते रहे।

इसी प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण अपने 25 वर्ष की सेवा यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के कल्याण, मध्यम वर्ग को मजबूत करने, महिलाओं को सशक्त बना नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास, किसान हितैषी नीतियों के जरिए बुवाई से लेकर हर चरण में अन्नदाताओं की चिंता का समाधान किया है। युवाओं के लिए शिक्षा-रोजगार के अवसर, सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता के साथ राष्ट्र के विकास को सदैव प्राथमिकता दी है। विकासवाद को मुख्यधारा में लाकर अन्य सामाजिक कुरीतियों को धराशायी किया गया और विकास देश की राजनीति, कार्यनीति और राष्ट्रनीति का मुख्य आधार बन गया। 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हर नीति निर्माण और एक्शन में 'भारत प्रथम' को सर्वोपरि रखा। उसी संकल्प ने उन्हें कठोर से कठोर निर्णय लेने का साहस प्रदान किया। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हो या उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विदेशों में भी भारतीय हितों के साथ-साथ मानवता के कल्याण की सोच का नेतृत्व किया। डिजिटल क्रांति से लेकर खुले में शौच से मुक्ति, कोविड के स्वदेशी टीकों से अपने नागरिकों के साथ-साथ विश्व मानवता को सुरक्षित करना, निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि तक पहुंचना, ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिसे अतीत में असंभव मानकर नियति के भरोसे छोड़ दिया गया था। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सेवाओं और योजनाओं की पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना, हर नागरिक तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना, प्रधानमंत्री मोदी के शासन में सकारात्मक बदलाव के उदाहरण हैं। आज विज्ञान और तकनीक भारत के विकास का ऐसा उपकरण बना है कि प्रशासनिक सुधार, बिजली, रेल सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश, टैक्स पारदर्शिता, जीएसटी से एक देश-एक टैक्स, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, किसानों-महिलाओं के हित में कदम, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव से लेकर रक्षा आधुनिकीकरण और दशकों से लंबित ऐसी परियोजनाएं साकार हो रही हैं, जो पहले असंभव लगती थी।

केंद्र सरकार ने विभिन्न उपेक्षित समूहों का सशक्तीकरण सुनिश्चित कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है, ताकि वे भी आत्मनिर्भर हो सके। केंद्र सरकार ने हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि कोई भी व्यक्ति विकास की राह में पीछे न छूट जाए, इसलिए बीते कुछ वर्षों में जनकल्याण से जगकल्याण की सोच प्राथमिकता बनी है। यही कारण है कि अब सरकार ने अमृत काल में सभी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पर्यावरण से संबंधित फैसले हों या भारतीय संस्कृति के संरक्षण के, दुनिया भर में भारत की समृद्ध विरासत और सभ्यता को नया स्वरूप मिला है। प्रधानमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन में सदैव लोगों के भीतर आकांक्षाएं पैदा की है और उसे पूरा करने के लिए जन-जन को प्रेरित किया है। आज देश की रीति-नीति बदली है और नई परंपराएं उदीयमान हुई हैं तो यह प्रधानमंत्री मोदी की विशिष्ट कार्यशैली की वजह से ही है। त्वरित निर्णय, तीव्र गति से कार्रवाई, गांव-गरीब की फिक्र, तकनीक के साथ विकास और जीवन स्तर में सुधार, आज यथार्थ हो रहे हैं। उन्होंने 2047 तक एक मजबूत, समृद्ध, समावेशी और विकसित भारत बनाने के लिए अमृत काल के रूप में राष्ट्र को एक नया संकल्प दिया है। उसे साकार करने के लिए जन-जन को प्रेरित भी किया है।

कर्तव्य पथ को जीवन पथ बना बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र ने निर्णायक फैसले लिए, ताकि एक मजबूत नींव के साथ जब देश अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो तब विकासशील से विकसित देशों की कतार में खड़ा हो सके भारत। ऐसे में जब पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में अनवरत जारी उनकी शासन यात्रा 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही है तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सरकार के ऐसे 25 निर्णय जो बन गए हैं अमृत यात्रा का आधार और अमृत काल के संकल्प को साकार करने का विकासरूपी संस्कार...

01

राष्ट्रीय सुरक्षा...निर्णायक कार्रवाई का एक दशक

- 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर यह बता दिया कि यह नया भारत है।
- 28-29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक और 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया।
- वर्ष 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 2025-26 में रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये किया गया।
- डिफेंस कॉरिडोर जैसी पहलों से स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा। रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा।
- रक्षा निर्यात 2013-14 के 686 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ रुपये पहुंचा।
- रक्षा क्षेत्र से जुड़े 5,012 सामान स्वदेशी उद्योगों से खरीदने की पहल।
- रक्षा उत्कृष्टता में इनोवेशन के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडीईएक्स) की पहल।
- सुदर्शन चक्र मिशन के जरिए वर्ष 2035 तक एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच बनाने की शुरुआत की गई।

02

नई परंपराओं का उदय

पद्म पुरस्कार

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई, ताकि कोई भी आवेदन कर सके। नतीजा, गुमनाम रहे नायकों को सम्मान मिला।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी को पेश करने की शुरुआत की, ताकि नए बजट के हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था को एक महीने तैयारी का समय मिल सके। रेल और आम बजट का एकीकरण किया।
- लंबे समय से लटके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजिल तक पहुंचाने के लिए 'प्रगति' प्लेफार्म की शुरुआत की गई। इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी खुद करते हैं।
- लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में पीएम मोदी ने प्रचलित परंपराओं के विपरीत शौचालय, सैनेटरी पैड जैसे शब्दों का उपयोग कर जन मानसिकता को बदलने की शुरुआत की।
- 'मन की बात' और 'परीक्षा पे चर्चा' के जरिए संवाद की अनोखी शुरुआत। अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित बनाने का विराट संकल्प।

03

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख: विकास की नई सुबह

एक देश-एक विधान-एक प्रधान का सपना 6 दशक बाद हुआ साकार...तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तक पहुंचा विकास का उजियारा...

- 5 अगस्त 2019 को, देश की संसद ने जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में ऐतिहासिक सुधार किया। जम्मू-कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से अलग करने वाले अनुच्छेद 370 और 35-ए को निष्प्रभावी बनाया गया।
- जम्मू-कश्मीर में 890 से अधिक केंद्रीय कानून लागू किए गए।
- लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
- पथराव की घटना में 100 प्रतिशत की गिरावट दर्ज, यह शांति के नए युग को दर्शाता है।

चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज (359 मीटर) शुरू किया गया।

"कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह ताज और सुंदर हो और समृद्ध हो। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

04 नए भारत के केंद्र में नारी शक्ति

- मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया।
- लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का लिया गया निर्णय।
- महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- तीन तलाक की कुप्रथा को किया गया समाप्त।
- 2014 में रक्षा क्षेत्र में 3,000 महिला अधिकारी अब 11,000 से अधिक।

लखपति दीदी योजना

2025 तक 3.35 करोड़ संभावित महिला लाभार्थियों की पहचान, डिजिटल आजीविका के तहत 8.7 करोड़ महिलाओं को पंजीकृत किया गया है।

एनडीए में महिला कैडेट को शामिल करने का लिया गया निर्णय।

पोषण 2.0 को 1.81 लाख करोड़ रु. के निवेश के साथ शुरू किया गया।

05 युवा आकांक्षाओं को मिली उड़ान

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से गैर राजनीतिक परिवार से एक लाख युवाओं को राजनीति में आने की अपील। युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, कौशल विकास, डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी सरकारी पहल शुरू की गई।

- 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की घोषणा की, इस पर एक लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान, लक्ष्य दो वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 :** प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर उच्च एवं व्यावसायिक स्तर तक शिक्षा की पहुंच। वर्ष 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100 प्रतिशत और 2035 तक उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का लक्ष्य।
- राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम जैसी पहल से युवा नेतृत्व, सेवा और नागरिक सहभागिता में बदलाव ला रहे हैं।

131% की बढ़ोतरी, युवा मामले और खेल मंत्रालय के बजट में 2014 के मुकाबले।

रोजगार मेला : 2022 में शुरू किया, 16 राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के माध्यम से सरकारी नौकरियों के लिए लगभग 10 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।

06

आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बन रहे किसान

किसान भारतीय कृषि की नींव हैं जो भोजन सुनिश्चित करते हैं। बीते वर्षों में सुधार, नई तकनीक और बढ़ते सरकारी समर्थन ने कृषि और किसान को मजबूती दी है। बीज से बाजार तक किसानों को सुरक्षा कवच देकर बना रहे हैं आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध...

- कृषि का बजट 2013-14 के मुकाबले 6 गुना से अधिक बढ़ा।
- लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य हुआ सुनिश्चित।
- पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 4 लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचे।
- सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए राष्ट्रीय औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% लाभ के साथ एमएसपी में वृद्धि की है।

07

भारत के समावेशी विकास की नींव... सामाजिक समरसता

पीएम मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र के साथ केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिक के लिए समानता, सामाजिक-आर्थिक न्याय और गरिमा कर रही है सुनिश्चित...

- देश के अति पिछड़े 112 जिलों के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम और फिर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाया गया है। वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पेंशन की व्यवस्था पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में की गई।
- 15.69 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचा, 2.86 करोड़ घरों तक सौभाग्य योजना में बिजली तो 10.33 करोड़ घरों में गैस का कनेक्शन।
- 56.21 करोड़ लाभार्थी पीएम जनधन योजना से बैंक से जुड़े। वहीं प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में 50 करोड़ से अधिक लाभार्थी।
- 4 गुना बढ़े एकलव्य मॉडल स्कूल तो 1.6 करोड़ युवा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में किए गए प्रशिक्षित।

08 गरीब कल्याण सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बना

अंत्योदय की सोच ने अंतिम छोर के लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं की पहुंच मुमकिन बनाई तो 10 वर्षों में ही 25 करोड़ लोग आए गरीबी से बाहर...

- पेयजल, बिजली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शौचालय, रसोई गैस सिलेंडर, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गारंटी गरीबों के जीवन का सहारा बनी।
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए लगभग 81 करोड़ लोगों को भोजन की गांरटी।
- मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण अभियान के जरिए कुपोषण के खात्मे की शुरुआत।
- पीएम आवास योजना के जरिए 4 करोड़ से अधिक लोगों का घर का सपना साकार।
- स्वच्छ भारत मिशन के जरिए 12.50 करोड़ से अधिक परिवारों को शौचालय मिला।
- सौभाग्य योजना से आजादी के बाद भी बिना बिजली रह रहे लोगों तक पहुंची इलेक्ट्रिसिटी।
- पीएम स्वनिधि ने पहली बार रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खोला बिना शर्त ऋण का रास्ता।

09

विकास के केंद्र में मध्यम वर्ग

- 11 साल में 4 बार आयकर छूट का उपहार। अब वेतनभोगियों के लिए 12 लाख रुपये तक वेतन आयकर मुक्त, साथ में 75 लाख रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ। 88 फीसदी करदाता अब टैक्स फ्री ।
- आयकर अधिनियम, 2025 के साथ पुराने ढांचे के मूल प्रावधानों को बरकरार रख आसान बनाया।
- आयकर रिटर्न फाइलिंग में 135% बढ़ोतरी।
- मार्च 2015 के 5.17% के मुकाबले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 1.55% पर आई।
- रिटायर होने वाले कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए यूनीफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत।
- उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के जरिए अब हवाई यात्रा मध्यम वर्ग के दायरे में।
- घर खरीददारों के हित की रक्षा के लिए रेरा कानून लागू।

10

दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर कदम

- पिछले 11 वर्षों में, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान से शीर्ष पांच में पहुंच गई है।
- वर्ष 2030 तक भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है।
- 8 साल पहले सबसे बड़े कर सुधार के रूप में लागू हुई जीएसटी। अब जीएसटी 2.0 के तहत मुख्य रूप से दो स्लैब (5 और 18%) में किया गया।
- जून, 2025 में विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार।
- 825 अरब डॉलर का रिकॉर्ड वस्तु एवं सेवा निर्यात 2024-25 में।
- पीएलआई के तहत 1.76 लाख करोड़ का निवेश, 16.5 लाख करोड़ का उत्पादन, 12 लाख रोजगार सृजन।
- दुनिया के कुल डिजिटल भुगतान में 50% हिस्सा यूपीआई का।
- मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती। हम अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता।

11

सरकार ने संभाली स्वास्थ्य की जिम्मेदारी

70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग को पीएम-जय योजना का लाभार्थी बनाया गया।

- **आयुष्मान भारत-पीएम-जय :** देश की करीब 60 करोड़ आबादी को हर वर्ष पांच लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी गई।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत :** टेलीमेडिसिन सेवा से लेकर एक क्लिक पर स्वास्थ्य रिकॉर्ड।
- **50 से 90% तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा:** प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है ।
- कोविड-19 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया।
- मोटापा कम करने के लिए एक जनआंदोलन की शुरुआत, खाद्य तेल में 10 फीसदी कटौती का आह्वान।

12

पूर्वोत्तर: नए भारत की विकास गाथा का गेट-वे

कभी हिंसा और नाकाबंदी के लिए पहचान रखने एवं 5 करोड़ से अधिक आबादी वाला यह हिस्सा अब विकास पथ पर चलते हुए सर्वांगीण विकास का साक्षी बन रहा है। बीते 11 वर्षों में कनेक्टिविटी, उद्यमिता और रणनीतिक प्रासंगिकता के केंद्र में बदला...

- पूर्वोत्तर क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी मानकर विकास यात्रा शुरू की।
- वर्ष 2014 के मुकाबले बजट आवंटन में ढाई गुना बढोतरी।
- 1 जून 2025 तक, पूर्वोत्तर के 92 प्रतिशत गांवों तक मोबाइल और 4 जी कनेक्टिविटी पहुंची।
- 2014 के बाद से त्रिपुरा शांति समझौता, बोडो शांति समझौता, कार्बी-आंगलोंग शांति समझौता, असम-मेघालय सीमा समझौता, असम में आदिवासी शांति समझौता, डीएनएलए शांति समझौता, उल्फा शांति समझौता, एनएससीएन (आईएम) के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एनएलएफटी और एटीटीएफ शांति समझौता।
- इन शांति समझौतों की पहल से समृद्धि के नए युग की शुरुआत।

64% की कमी उग्रवादी घटनाओं में वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2024 में।

"जहां पूर्वोत्तर कभी मात्र सीमावर्ती क्षेत्र माना जाता था, वहीं अब यह भारत की विकास गाथा में अग्रणी बनकर उभर रहा है।" **-नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

13

डिजिटल दशक... तकनीक से तरक्की की यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेकसेवी राजनेता से पीएम तक का सफर ही तय नहीं किया, बल्कि तकनीक के जरिए आम आदमी के जीवन में सुविधाओं तक इसे उतारा भी...

- तकनीक के जरिए अंतिम छोर के लाभार्थी तक पहुंच संभव हुई। डीबीटी से सीधे खाते में पहुंचा लाभ तो 3.48 लाख करोड़ रुपये की हुई बचत।
- वर्ष 2029-30 तक देश की राष्ट्रीय आय में 5वां हिस्सा डिजिटल अर्थव्यवस्था का होगा।
- एआई इनोवेशन के लिए भारत एआई मिशन की शुरुआत।
- भारत सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाने की शुरुआत।
- अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला।
- इंटरनेट सबसे सस्ता। अब 2014 के मुकाबले 285% की बढ़ोतरी के साथ 96.91 करोड़ इंटरनेट ग्राहक।
- भारतनेट के जरिए करीब 7 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर बिछा गांवों तक इंटरनेट पहुंचाया। पीएमजीदिशा के जरिए कुल 6.39 करोड़ ग्रामीण प्रशिक्षित।

14

अब दंड नहीं, मिल रहा न्याय, सुगमता का नया युग

देश में नया कानून

भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता का कानून लाया गया।

नए आपराधिक कानून

देश में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून को पीड़ित केंद्रित बनाया गया।

- आजादी के 77 वर्ष बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हुई।
- नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को प्राथमिकता दी गई।
- नए कानूनों में अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह का कानून पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।
- किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिलेगा।

15

विकास और विरासत का मंत्र भारत की प्रगति का आधार

- 127 वर्षों के बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लाया गया भारत।
- 2025 में भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को में जोड़ा गया।
- 642 पुरावशेषों को 2014 के बाद से भारत ने प्राप्त किया।
- 1.18 लाख पुरावशेषों और कलाकृतियों का एएसआई ने राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन के तहत डिजिटल अभिलेखीकरण किया है।
- 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु केवल एक महीने में महाकुंभ 2025 में शामिल हुए।
- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर, राम मंदिर, गुजरात में जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, भ्रमण पथ और पार्वती मंदिर का विकास।
- तीर्थयात्रा के लिए संपर्क में बढ़ोतरी के लिए चार धाम राजमार्ग परियोजना, हेमकुंड साहिब रोपवे, बौद्ध सर्किट, करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर काम।

1 करोड़ के करीब विदेशी पर्यटक 2024 में भारत आए।

"सांस्कृतिक धरोहर सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि यह मानवता की साझा चेतना है। जब भी हम ऐतिहासिक स्थलों को देखते हैं, तो हमारी सोच मौजूदा भू-राजनीतिक हालात से ऊपर उठ जाती है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

16

जनजातीय सशक्तीकरण के जरिए समावेशी भारत का निर्माण

- 25,000 करोड़ रुपये से कम बजट था जनजातीय क्षेत्रों और परिवारों के विकास के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने इसे पांच गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपये कर दिया।
- 4,000 से अधिक वन धन केंद्र देश भर में चल रहे हैं, जिनमें 12 लाख जनजाति शामिल हैं। उन्हें आजीविका का एक बेहतर साधन मिला है।
- 15 नवंबर को भारत सरकार हर साल भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस मनाती है।
- 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य।
- 30 लाख करीब जनजातीय छात्रों को पांच केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं से सालाना लाभ मिलता है।
- 2023 में जनजातीय आबादी में स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत। 6 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों की अब तक स्क्रीनिंग।
- 117 ट्राइब्स इंडिया रिटेल स्टोर भारत में। इसने 13,000 से अधिक जनजातीय उत्पादों को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों पर डाला।
- 2014 से 2024 के बीच, अनुसूचित जनजातियों की सूची में 117 समुदायों को शामिल किया गया, जबकि पिछले दशक में केवल 12 को शामिल किया गया था।

17

ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्थिरता और इनोवेशन की दिशा में बढ़ता भारत

भारत न केवल अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ा रहा है, बल्कि उसे नया रूप भी दे रहा है। पिछले एक दशक में भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्थिरता और नवाचार की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव की तरफ तेजी से बढ़ाए कदम...

250 गीगावाट हुई गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन क्षमता जो कुल क्षमता के 50% से अधिक है।

60% की वृद्धि हुई वार्षिक परमाणु विद्युत उत्पादन में जबकि स्थापित परमाणु क्षमता में 71% की वृद्धि।

- नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है भारत, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर और सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर है।
- 490 गीगावाट तक पहुंची अगस्त 2025 तक, कुल स्थापित बिजली क्षमता जो 2015-16 में 305 गीगावाट थी। बिजली की कमी 2013-14 में 4.2% से घटकर अब 0.1% रह गई। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में 45.8% की वृद्धि हुई। छह गुना बढ़े पीएनजी कनेक्शन तो 10 गुना ज्यादा बढ़े सीएनजी स्टेशन।
- 100% शहरी गैस वितरण कवरेज जनसंख्या के हिसाब से पहुंची जो 2014 में 13.27% थी। क्षेत्र के हिसाब से 5.58% से बढ़कर लगभग 100% हो गया।
- बिजली उत्पादन 2015-16 के 1,168 बिलियन यूनिट से बढ़कर 2024-25 में 1,827 बिलियन यूनिट हो गया।

18

सतत विकास कोई सपना नहीं, एक जीवंत वास्तविकता

भारत का हरित परिवर्तन सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, यह एक जन आंदोलन, एक ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता और आने वाली पीढ़ियों से किया गया एक वादा है...

13 भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। भारत 2018 में ब्लू फ्लैग कार्यक्रम में शामिल हुआ।

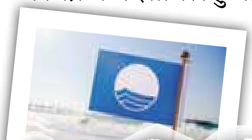

- भारत 'नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक' में 7वें स्थान पर है।
- भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन लांच किया गया जिसका मुख्यालय भारत में है। इसके 105 सदस्य देश हैं।
- मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, पीएम सूर्य घर योजना के साथ-साथ जलवायु कार्रवाई के लिए पांच प्रमुख लक्ष्य, 'पंचामृत' भी पेश किए।
- 130 अरब डॉलर पहुंची जैव अर्थव्यवस्था 2024 में, यह 2014 में महज 10 अरब डॉलर थी।

19

खेल : जमीनी स्तर से गौरव तक

- भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिससे वैश्विक मंच पर अपनी खेल उत्कृष्टता का प्रदर्शन होगा।
- 1 जुलाई, 2025 को खेलो भारत नीति, 2025 शुरू की गई।
- वित्त वर्ष 2016-17 में शुरू किए गए खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जन भागीदारी और खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।
- 18 अगस्त, 2025 को लागू राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025, भारतीय खेल प्रशासन में एक ऐतिहासिक सुधार का प्रतिनिधित्व करता है।
- कीर्ति (खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन) 9 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच खेल प्रतिभा की पहचान करने और पोषण करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल।
- मणिपुर के इंफाल में 2018 में स्थापित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और कोचिंग में खेल शिक्षा के लिए एक समर्पित संस्थान।

20 इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के 11 वर्ष... विकास पथ में वृद्धि

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक यज्ञ पिछले 11 वर्ष से चल रहा है। बीते 11 वर्ष में हुई इस क्रांति ने देश में उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा जोड़ा है। रेल से लेकर राजमार्गों, बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक, भारत का त्वरित गति से बढ़ता इंफ्रा नेटवर्क 'ईज ऑफ लिविंग' और देश की समृद्धि को दे रहा है बढ़ावा...

- पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान, उड़ान, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत जैसी योजनाओं ने हाइवे, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट और शहरी जीवन की सुविधाएं विकसित करने में मदद की है। जैसे-जैसे भारत भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक नींव नहीं, लांच पैड साबित हो रहा है।
- 7.8 लाख किलोमीटर पूरी हुईं 2014-25 तक ग्रामीण सड़कें।
- भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे केवल 500 दिनों में पूरा हुआ।
- विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च चिनाब ब्रिज और भारत का पहला केबल-स्टे रेल ब्रिज (अंजी ब्रिज) का जून, 2025 में उद्घाटन किया गया।
- 31,000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों को 2014 के बाद जोड़ा गया तो करीब 47 हजार किलोमीटर रेल विद्युतीकरण किया गया। सुरक्षा के लिए विभिन्न मार्गों पर कवच तैनात।

144
वंदेभारत ट्रेन चल रही है जबकि विश्वस्तरीय अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल की भी शुरुआत।

1,46,342
किलोमीटर हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, 2014 में 91,287 किलोमीटर था।

- 1,000 किलोमीटर से ऊपर पहुंचा मेट्रो रेल का नेटवर्क, 2014 में था 248 किलोमीटर। 2.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश इस क्षेत्र में किया गया, घरेलू स्तर पर 2000 से अधिक कोच बनाए गए।
- पोर्ट की क्षमता बीते 11 वर्ष में दोगुना हुई तो टर्नअराउंड समय में 93 से 48 घंटे तक सुधार।
- 1.12 लाख करोड़ रुपये के काम अमृत योजना में पूरे हुए तो वहीं स्मार्ट सिटी मिशन में 1.64 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

21 स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम

भारत पिछले एक दशक में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। भारत के युवा अब नौकरी चाहने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में कहें तो ''स्टार्टअप एक सामाजिक संस्कृति बन गई है और कोई भी सामाजिक संस्कृति को रोक नहीं सकता।''

- पहले स्टार्टअप का नाम भी सुनाई नहीं देता था, लेकिन बीते 11 वर्षों में ही अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईको-सिस्टम बना।

118
के पार यूनिकॉर्न की संख्या पहुंच गई।

22 नए संस्थानों की स्थापना बड़े बदलाव का रास्ता...

- 6 दिसंबर, 2024 तक, 49 लाख से अधिक सिविल सेवक और 1,500 से अधिक पाठ्यक्रम आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल हो चुके हैं।
- वर्ष 2021 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना।
- नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की स्थापना, योजना आयोग की ली जगह।
- 2020 में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, मिशन कर्मयोगी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना।

2.7
करोड़ से अधिक पाठ्यक्रम नामांकन आईगॉट प्लेटफॉर्म पर।

"मिशन कर्मयोगी, क्षमता निर्माण की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को अपनी सोच, दृष्टिकोण और कौशल में सुधार करके आधुनिक बनाना है। उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर प्रदान करना है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

23 आजादी के अमृत महोत्सव में जनभागीदारी का जन उत्सव

- 12 मार्च 2021 को दांडी यात्रा की प्रेरणा से आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई।
- 31 अक्टूबर 2023 को सरदार पटेल की जयंती पर "मेरी माटी मेरा देश" अभियान के साथ संपन्न। यह महोत्सव करीब एक हजार दिन चला। मिट्टी के साथ देशभर से जो पौधे आए, उसे शामिल कर इंडिया गेट पर अमृत वाटिका बनाने की शुरुआत।
- महोत्सव के समापन समारोह पर मेरा युवा भारत संगठन, यानी **MY** भारत की नींव रखी गई है। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा किया। देश ने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया।
- अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस, साहेबजादों की याद में वीर बाल दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। देशभर में 65 हजार से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया।
- आजादी के गुमनाम नायकों को याद किया गया। आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहे सेनानियों का जिलावार एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी तैयार हुआ
- आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान 2 लाख से अधिक कार्यक्रमों के आयोजन से पूरे देश में एक बार फिर देशभक्ति की भावना जागृत हुई।

24 विकसित भारत @2047

- **पांच स्तंभों पर खड़ा है आत्मनिर्भर भारत :** अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी या युवा आबादी और मांग।

भारत मोबाइल निर्माण में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बन गया है, वर्ष-2014-15 में।

18,000 करोड़ रुपये का उत्पादन जो बढ़कर वर्ष 2024-25 में 5.45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा।

- कोविड-19 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने से रोकने के लिए पीएम मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था, ये दो शब्द आज हर भारतीय की प्रेरणा है।
- 'आत्मनिर्भरता' को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2020 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया।
- पीएम मोदी ने 'वोकल फॉर लोकल' को जीवन का मंत्र बनाने की अपील की है। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है।
- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन :** खनिज में आत्मनिर्भर बनने के लिए 1,200 स्थलों की खोज की जा रही है।
- पिछले 11 वर्षों में भारत का रक्षा क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक से स्वदेशी उत्पादन के उभरते केंद्र में बदल गया है।

25 देश में बढ़ा मान, दुनिया में सम्मान

- जी-20 की अध्यक्षता में भारत ने नई दिल्ली घोषणापत्र और अफ्रीकन यूनियन को इस समूह से जोड़कर कीर्तिमान गढ़ा।
- प्रवासियों के हितों को भारतीय दूतावासों-मिशन के जरिए प्राथमिकता।
- भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की और इसका मुख्यालय भारत में बना।
- वर्ष 2014 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) घोषित किया गया। भारत के सॉफ्ट पॉवर वाली भूमिका दुनिया देख रही है।
- क्वाड, एससीओ, ब्रिक्स, जी-20, यूएन सुरक्षा परिषद सहित विभिन्न मंचों पर भारत महत्वपूर्ण भूमिका में।
- 23 हजार से ज्यादा लोग यूक्रेन से युद्ध के बीच भारत लाए गए। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानों का सफल संचालन किया गया।
- कोविड के दौरान अपनों की घर वापसी के लिए मिशन वंदे भारत चलाया गया। जून 2014 में इराक से 46 भारतीय नर्सों को वापस लाया गया। अफगानिस्तान संकट के बीच ऑपरेशन देवी शक्ति से घर पहुंचे भारतीय।
- यमन में ऑपरेशन राहत: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कॉल से निकला भारतीयों की वापसी का रास्ता।
- ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से 4 हजार से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी।
- 1,300 से ज्यादा लोगों को ऑपरेशन अजय में इजरायल से निकाला गया।
- कतर में भारतीय नौसेना के सभी आठ पूर्व सैनिक रिहा कराए गए।
- ऑपरेशन इंद्रावती के साथ हैती में अभियान।

153 लोगों को ऑपरेशन संकटमोचन के तहत दक्षिण सूडान से स्वदेश लाया गया।

राष्ट्र का ऐतिहासिक दिवाली उपहार
नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार

भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वर्णिम युग का आरंभ

हर देश की विकास यात्रा में एक ऐसा समय आता है जब वह स्वयं को नए सिरे से परिभाषित करता है, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ता है। अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार, त्योहारों के इस मौसम में उसी सिद्धि का मार्ग दिखाकर भारत की विकास यात्रा का उत्सव बन गया है। 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि के समय संघवाद का उम्दा उदाहरण पेश करते हुए देश ने 17 साल के कठिन संघर्ष की यात्रा को यथार्थ में बदला था। अब अपने 9वें वर्ष की यात्रा में परिवर्तनकारी सुधार का उत्सव मना रही जीएसटी 22 सितंबर 2025 से नए युग का आरंभ कर रही है। आम नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव, उद्यमियों को सरलता और अगली पीढ़ी को सशक्त करने वाले केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से शुरू हो चुकी है भारत की विकसित होती अर्थव्यवस्था की नई कहानी...

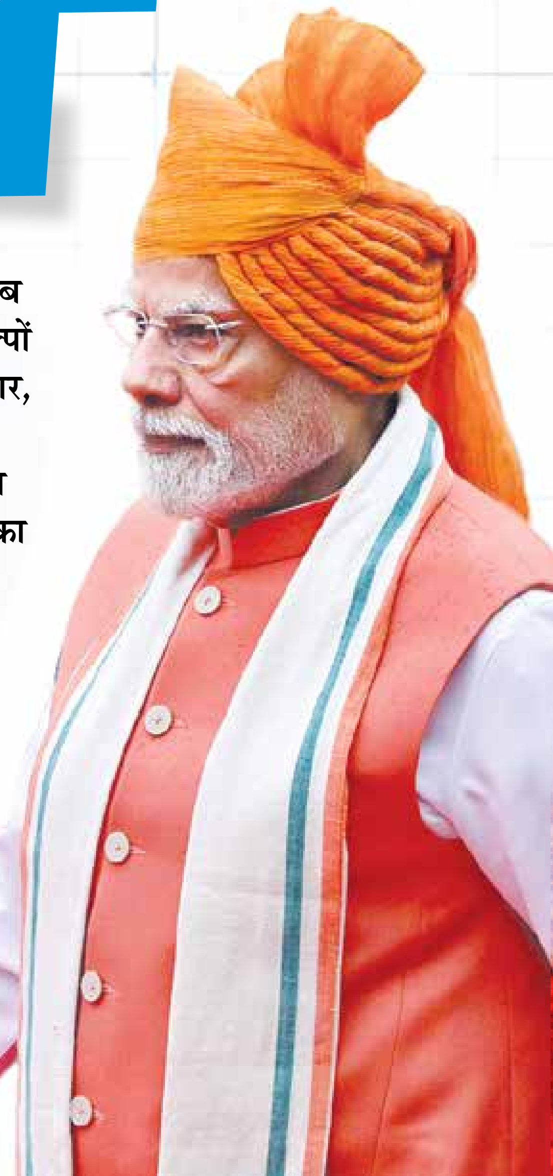

यह सुधार का उत्सव है। निरंतरता में साहसिक निर्णय का उत्सव है। कुल मिलाकर यह भारत के विकास का उत्सव है, जो इस त्योहार में सभी वर्गों से जुड़े परिवारों में खुशियों की लहर लेकर आया है। लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म (अगली पीढ़ी का सुधार) करना बहुत जरूरी है। उन्होंने दिवाली और छठ पूजा से पहले नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार का उपहार देने का वादा किया था। इस दिवाली से पहले क्रांतिकारी सुधार लागू भी हो रहे हैं। अब जीएसटी में चार की जगह मुख्य रूप से केवल दो दरें 5 व 18 प्रतिशत ही रह गई हैं। वहीं विलासिता वाली चुनिंदा वस्तुओं और नागरिकों के हानिकारक वस्तुओं के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए 40% का अलग स्लैब बनाया गया है। नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले इन सुधारों से करोड़ों परिवारों की खुशियां दोगुनी हो गई हैं।

आठ वर्ष पहले 30 जून-1 जुलाई की मध्य रात्रि को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से जब जीएसटी की शुरुआत हुई, तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। यह आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक बना था। इस अर्थक्रांति से राष्ट्र ने आर्थिक समृद्धि के नए युग में प्रवेश किया था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाई गई थी। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन सुधार की आवश्यकता थी, जिसे निरंतरता के साथ साकार किया गया है। जीएसटी 2.0 देश की प्रगति का डबल डोज बनकर आया है। यानी एक तरफ इससे देश के सामान्य परिवारों की आर्थिक बचत होगी तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। जीएसटी की दरों में कमी से गरीब, नव मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, महिला, छात्र, युवा सभी को बड़ा लाभ मिलेगा। पनीर से लेकर शैंपू-साबुन तक, सब कुछ पहले से कहीं अधिक सस्ता होगा। इससे रसोई पर होने वाले मासिक खर्च में बड़ी कमी आएगी। स्कूटर-कार पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसका बहुत फायदा उन युवाओं को होगा, जो अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं। जीएसटी कम होने से घर का बजट और बेहतर जीवनशैली में नागरिकों को मदद मिलेगी।

सशक्त, पारदर्शी और समावेशी सुधार

इच्छा + स्थिरता = संकल्प

संकल्प + पुरुषार्थ = सिद्धि

आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने के लिए नई पीढ़ी के सुधार

जीएसटी सरल ही नहीं, जनहितकारी भी हो। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी की इसी उद्घोषणा के साथ 3 स्तंभों को जोड़कर अब तक के सबसे बड़े जीएसटी सुधार की नींव रखी गई, ताकि आम जनता, किसान, मध्यम वर्ग और एमएसएमई तक सीधा लाभ पहुंचे। साथ ही, आत्मनिर्भरता के साथ विकसित भारत की राह में आगे बढ़ते देश के लिए यह सुधार सिर्फ सीढ़ी का एक पायदान भर नहीं, बल्कि है मजबूत उभरता स्तंभ...

संरचनात्मक सुधार

- संरचनात्मक बदलाव करके चार स्लैब को दो स्लैब दर किया गया है। यह बदलाव दो मुख्य क्षेत्रों में इनवर्टेड इ्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार को ध्यान में रख कर किए गए हैं। जिनमें मैन मेड टेक्सटाइल सेक्टर और उर्वरक क्षेत्र के साथ-साथ वर्गीकरण विवादों को हल करने के लिए क्षेत्रवार दरों को तर्कसंगत बनाना शामिल है।
- मैन मेड टेक्सटाइल सेक्टर और उर्वरक क्षेत्र के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या का समाधान किया गया है। नियमों का पालन करने वाले करदाताओं को रिफंड आसानी से उपलब्ध होगा और कार्यशील पूंजी अटकेगी नहीं। जीएसटी कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि इनपुट पर कर की दर आउटपुट पर लगने वाली दर से अधिक होने के कारण उत्पन्न इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड दावे (जिसे सामान्य रूप से 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' कहा जाता है) की 90% राशि को, रिफंड दावे की विस्तृत जांच लंबित रहते हुए, अनंतिम रूप से प्रदान किया जा सके। जब तक कानून में संशोधन नहीं हो जाता, तब तक सीबीआईसी अपने अधिकारियों को निर्देश जारी करेगा कि वे जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सिस्टम द्वारा चिन्हित करदाताओं को 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' के आधार पर दाखिल रिफंड दावों में दावे की राशि का 90% अनंतिम रिफंड के रूप में प्रदान करें।
- नियमों में संशोधन किया जाएगा ताकि शून्य-मूल्य आपूर्ति वाले माल या सेवाओं या दोनों के रिफंड के रूप में दावा की गई राशि के 90% के बराबर अनंतिम रिफंड स्वीकृत करने का प्रावधान किया जा सके। यह अनंतिम रिफंड उपयुक्त अधिकारी द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।
- वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण में स्पष्टता, ताकि कर से संबंधित भ्रम और विवाद कम हो सकें।
- उद्योगों के लिए दीर्घकालिक स्थिर कर नीति, ताकि वे बेहतर योजना बना सकें।
- वस्तु और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) दिसंबर 2025 तक कार्यशील हो जाएगा।

फायदा

इससे टैक्स का कैलकुलेशन आसान होगा, विवाद कम होंगे और कारोबारियों के लिए नियमों का पालन करना आसान होगा। न्यायाधिकरण के जरिए किसी भी विवाद का आसानी से निपटारा हो सकेगा।

दरों का सरलीकरण

- दरों को युक्तिसंगत बनाने में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए जटिल बहु-स्लैब प्रणाली को सरल बनाया गया है।
- इसके तहत 5%, 12%, 18% और 28% (कुछ वस्तुओं पर उपकर सहित) की पुरानी संरचना को मोटे तौर पर दो-स्तरीय प्रणाली द्वारा 5% मेरिट दर (आवश्यक और आम इस्तेमाल की वस्तुओं के लिए), 18% मानक दर (अधिकांश अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए) है।
- विलासिता वाली चुनिंदा वस्तुओं के लिए 40% की विशेष दर तय की गई है। यह विशेष दर इन पर पुराने 28% से अधिक उपकर (जहां भी यह लागू है) स्लैब की जगह लेती है।
- इसके तहत 391 वस्तुओं की दरों में बदलाव किया गया, जबकि 357 वस्तुओं पर वर्तमान में लागू जीएसटी दरों में कमी की गई है।

फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, दरों में कटौती से करीब 93 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। हालांकि, 40 फीसदी के नए स्लैब से 45 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। इससे लगभग आधे घाटे की भरपाई हो जाएगी। इसके साथ ही, कीमतें कम होने से उपभोक्ता खर्च में होने वाली बढ़ोतरी भी इसकी भरपाई कर देगी। अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

ईज ऑफ लिविंग

- इसमें जीवन और व्यापार में सुगमता के लिए प्रक्रियागत सुधारों को लागू करना शामिल है।
- छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया डिजिटल और सरल की गई है। इसमें आवेदन करने के 3 कार्य दिवसों के भीतर ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसका लाभ लगभग 96% नए आवेदकों को होगा। यह भी 1 नवंबर 2025 से लागू होगी।
- टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब पहले से भरे हुए फॉर्म उपलब्ध हैं, जिससे गलती की आशंका घटी और समय की बचत हुई है। रिफंड की प्रक्रिया तेज और स्वचालित हुई, खासकर निर्यातकों और उन व्यापारियों के लिए जो इनवर्टेड ड्यूटी ढांचे के तहत आते हैं।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले छोटे सप्लायर्स के लिए आसान रजिस्ट्रेशन, अभी अलग-अलग राज्यों में सामान बेचने के लिए उन्हें हर राज्य में व्यापारिक पते की जरूरत होती है। अब उनके लिए आसान रजिस्ट्रेशन व्यवस्था बनाई जाएगी। इसकी विस्तृत प्रक्रिया बाद में जीएसटी काउंसिल के सामने रखी जाएगी।

फायदा

एक सरल और एकीकृत कर प्रणाली व्यापार की लागत घटाती है। निर्यात को बढ़ावा देती है। इससे भारत वैश्विक बाजार में और मजबूत व प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी बन सकता है। किराने के सामान से लेकर दवाई तक सस्ती होने से आम आदमी तक सीधा फायदा पहुंचा है तो नई व्यवस्था के साथ उद्योगों को भी लाभ मिला है। केवल दो दरों के चलते कंप्लायंसेस में भी कमी आएगी।

इसी मंत्र के साथ पहली जुलाई को वर्ष 2017 में अर्थनीति के एक ऐसे नए अध्याय का सूत्रपात हुआ था, जो भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। जीएसटी राष्ट्र निर्माण में सहयोग का एक माध्यम बनकर आया और 1 जुलाई 2017 की तारीख ने नई दिशा, नई गति, नए उमंग के साथ देश के सामान्य लोगों को ईमानदारी के उत्सव से जोड़ दिया। अब इसमें 22 सितंबर 2025 ने नया अध्याय जोड़ दिया है, जब देश के नागरिकों, व्यापारियों और अर्थव्यवस्था के लिए इसे अधिक सहज, सरल और लाभकारी बनाया गया है। जीएसटी प्रणाली में किया गया नया सुधार देश की जनता को राहत और आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। अब जीएसटी में मुख्य रूप से केवल दो दरों 5% और 18% वाली व्यवस्था लागू होगी। इस ऐतिहासिक कदम से आम जनता के साथ-साथ छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। यह सुधार देश को एक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के 7 स्तंभ

स्तंभ- 1
जीएसटीः से खुले नए रास्ते

- जीएसटी 2.0 कर प्रणाली को सरल बनाते हुए एक अधिक पारदर्शी द्विस्तरीय संरचना और तर्कसंगत दरों के साथ कर प्रक्रियाओं को सुगम बनाएगा।
- जीएसटी की शुरुआत ने 17 केंद्रीय और राज्य करों को एकीकृत कर एक देश-एक कर की व्यवस्था शुरू की थी। अब जीएसटी 2.0 में मुख्य रूप से केवल दो कर ढांचा देकर उसे तर्कसंगत और पारदर्शी बनाया है।

स्तंभ- 2
संतुलित कर व्यवस्था

- न्यायसंगत कराधान के लिए जीएसटी दरों को सरल बनाया गया।
- जीएसटी की दरें अब मुख्य रूप से केवल दो होंगी- 5 और 18 प्रतिशत, जो कि पहले की चार दरों से आसान हैं। इससे टैक्स विवाद में कमी होने के साथ ही रिफंड भी जल्दी मिलेगा।

स्तंभ- 3
टेक्नोलॉजी के जरिए फाइलिंग आसान

- छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए सरल पंजीकरण, 3 दिन में लाइसेंस और इससे 96 प्रतिशत नए पंजीकरणों को लाभ मिलेगा।
- निर्यातकों के लिए 90 प्रतिशत अग्रिम अनंतिम धन वापसी, छोटे निर्यातकों के लिए कोई सीमा नहीं। ई-इनवॉइसिंग और एआई तकनीक से जोखिम पहचान के साथ पूरी डिजिटल प्रक्रिया और नियमों का सही पालन सुनिश्चित।

स्तंभ-4
उपभोक्ताओं को प्राथमिकता नागरिक सुविधा प्रथम

- आवश्यक और ज्यादा खपत वाली वस्तुओं पर जीएसटी जीरो या 5 प्रतिशत तक के टैक्स स्लैब में किया गया।
- मोबिलिटी और बड़े घरेलू उपकरण (व्हाइट गुड्स) जैसे उत्पादों पर भी जीएसटी 28 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया।

स्तंभ- 5 : सशक्त एमएसएमई

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना- सशक्त होंगे एमएसएमई ।
- जीएसटी सुधार से छोटे निर्माताओं की नकदी प्रवाह की परेशानी कम होगी।
- आसान कर व्यवस्था के माध्यम से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी।

स्तंभ- 6
सरल कर संग्रह

- राज्यों के लिए लाभ- राजस्व बढ़ेगा और कर संग्रहण में सरलता आएगी।
- उपभोग बढ़ने से राजस्व में वृद्धि की संभावना।

स्तंभ-7 : समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति।
- घर-गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं सस्ती होंगी।
- मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर टैक्स बोझ कम होगा।
- उपभोग बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी।

किसान, सहकारिता- ग्रामीण उद्यमों के लिए वरदान

किसानों की जीवन गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य के साथ जीएसटी 2.0 के जरिए लागत में कमी के साथ मशीनीकरण पर खास फोकस, छोटे-मंझोले किसानों के साथ ग्रामीण उद्यमिता को मिलेगा बल, मजबूत होगी किसान-उन्मुख अर्थव्यवस्था...

खान-पान सस्ता

- **सभी डेयरी दूध-पनीर/छेना पर अब 5 की जगह शून्य कर, मक्खन और घी पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी। इससे 10 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को होगा लाभ।**
- **चॉकलेट, कॉर्न फ्लेक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक और बिस्किट पर 18% से घटाकर 5%, पैकिंग पेपर, डिब्बे और पेटियों पर केवल 5% जीएसटी।**

- लोहा, स्टील और एल्युमिनियम से बने दूध के कनस्तर पर अब 12% नहीं 5% जीएसटी। दुग्ध सहकारिताओं को मिलेगा लाभ।
- सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे चीज, नमकीन, पास्ता, जैम, जेली, फलों का गूदा और जूस आधारित पेय पदार्थ पर 18% या 12% की जगह 5% जीएसटी। घरेलू खर्च कम होगा, मांग बढ़ेगी और जुड़े सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
- अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी किया गया ताकि उर्वरक की उत्पादन लागत कम की जा सके। वहीं बारह बायो-पेस्टीसाइड और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 12% की बजाय 5% जीएसटी।
- मछली के तेल, अर्क, संरक्षित मछली के साथ झींगा उत्पाद व मछली पकड़ने की छड़ें, टैकल, लैंडिंग नेट, बटरफ्लाई नेट, गियर पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी।

1800 सीसी

से कम क्षमता वाले ट्रैक्टर पर 12% से 5% जबकि ट्रैक्टर के पुर्जों पर 18% की जगह 5% जीएसटी।

टायर-कृषि उपकरणों व सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर पर 12% से घटाकर 5% किया गया। छोटे डीजल इंजन पर 12% की जगह 5% जीएसटी की गई।

वाणिज्यिक ट्रक और डिलीवरी वैन पर 28% से घटाकर 18%

इससे प्रति टन/किलोमीटर भाड़ा कम होगा। लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं, मालवाहक वाहनों के थर्ड-पार्टी बीमा पर 12% की जगह 5% जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की सुविधा।

कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया गया निर्णय न केवल आमजन के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि व्यापार जगत और समग्र अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा प्रदान करेगा। इसी वर्ष आम जन को सुविधा, उद्यमियों को बल और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए जीएसटी में व्यापक सुधारों का आह्वान लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी उस संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक और निर्णायक कदम सिद्ध होगा। इन सुधारों से किसानों, लघु-कुटीर उद्योगों, छोटे व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी। देश भर में व्यापार और अधिक सरल व सुगम बनेगा। रोजमर्रा के घरेलू सामान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल पहले से अधिक सस्ता होगा। इन सुधारों से भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त, पारदर्शी और समावेशी बनेगी। इस जनहितैषी और साहसिक निर्णय से न केवल विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिलेगी, बल्कि हर परिवार लाभान्वित होगा, हर घर खुशहाल

अब सस्ती होगी बच्चों की पढ़ाई

जीएसटी 2.0 के तहत छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत दी गई है। अब स्टेशनरी जैसे नोटबुक, एक्सरसाइज बुक, नक्शे, पेंसिल और ड्राइंग के सामान पर टैक्स कर दिया गया है खत्म...

अब यह टैक्स फ्री

- सभी प्रकार के मानचित्र
- दीवार पर टांगे जाने वाले नक्शे
- टोपोग्राफिक प्लान
- ग्लोब ▪ पेंसिल
- शार्पनर ▪ पेंसिल
- क्रेयॉन (पेंसिल कलर)
- पेस्टल ▪ ड्राइंग चारकोल
- टेलर चॉक ▪ एक्सरसाइज बुक
- ग्राफ बुक ▪ लैब नोटबुक
- नोटबुक

अब 12% से घटाकर 0% हुआ टैक्स। वहीं, इरेजर पर 5% से 0% जीएसटी।

"आज देश में वो सरकार है जो राष्ट्र हित में बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार है। जीएसटी तो इतने सालों तक अटका ही इसलिए क्योंकि जो पहले सरकार में थे वो राजनीतिक जोखिम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमने न सिर्फ जीएसटी लागू किया बल्कि आज हम रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन होते देख रहे हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री"

फायदा

शिक्षा पर खर्च की लागत कम होगी। इससे सीधे परिवारों और छात्रों को मदद मिलेगी। इससे सीखने की सामग्री पर कम पैसा खर्च करना पड़ेगा।

होगा। इन सुधारों से ईज ऑफ लिविंग एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सशक्त करने में मदद मिलेगी। इससे सामान्य लोगों को खर्च करते समय कम टैक्स देना होगा, जिससे क्रय शक्ति बढ़ेगी। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया कि उनकी ओर से उठाए गए कदम न केवल तत्कालिक राहत देते हैं, बल्कि आने वाली पीढियों को सशक्त करने वाले होते हैं।

नागरिक देवो भव: के मंत्र से निरंतर सुधार

नागरिक जीवन हो या सरकार या संगठन, नदी के पानी की तरह गतिमान जीवन ही नई ऊर्जा का स्रोत बनता है। जब जीएसटी की शुरुआत हुई, तब वैश्विक अनुभवों और केंद्र-राज्य के वैचारिक मंथन से जीएसटी ने आकार लिया था। देश में आर्थिक एकीकरण की शुरुआत हुई थी। उसके बाद निरंतर सुधार की प्रक्रिया जारी रही और अब केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जीएसटी की व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव किए हैं। दरअसल, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कर प्रणाली महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में किसी भी सरकार की असली क्षमता का परीक्षण तब होता है जब वह ऐसी कर प्रणाली बनाए जो उत्पादन को बढ़ावा दे, खपत को प्रोत्साहित करे। साथ ही देश के राजस्व में भी उल्लेखनीय योगदान दे।

आठ वर्ष पूर्व, भारत ने "एक देश, एक टैक्स" के विजन को पूरा

कर मुक्त स्वास्थ्य सेवा की ओर सरकार के बढ़ते कदम

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आम आदमी तक सुलभ और किफायती दर पर पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। जीएसटी बदलाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन की दिखी साफ झलक...

स्वास्थ्य और जीवन बीमा अब जीएसटी फ्री

अब व्यक्तिगत टर्म लाइफ, यूएलआईपी, एनयूटी पेंशन, एंडाउमेंट पॉलिसी उनके पुनर्बीमा के साथ-साथ निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी और उनके पुनर्बीमा को जीएसटी मुक्त किया गया। पहले 18% जीएसटी दर थी।

दवाओं से लेकर चिकित्सा उपकरण तक सस्ते

- शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भौतिक या रासायनिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले कई चिकित्सीय उपकरणों और संयंत्रों पर अब 18% की बजाय 5% जीएसटी दर।
- चिकित्सीय उपकरण और आपूर्ति उपकरण जैसे वैडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट, रीजेंट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरण आदि पर जीएसटी अब 12% से घटकर 5% हुई।
- आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सहित अन्य दवाएं, बायो मेडिकल कचरे के अवशोषण अथवा निपटारे संबंधी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल विनिर्माण में जॉब वर्क, सूखे मेवे एवं मधुमेह के लिए विशिष्ट भोजन पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई।
- 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% की जगह शून्य, चिकित्सा ऑक्सीजन और थर्मामीटर पर 12-18 % की जगह 5% हुई।
- चश्मा और सुधारात्मक चश्मा 12 % नहीं 5% जीएसटी के दायरे में तो जिम एवं फिटनेस सेंटर पर अब 18% की जगह 5% जीएसटी।

फायदा

दवाओं, मेडिकल यंत्रों, पोषण एवं बीमा पर कर को कम किया गया है। स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। इससे 'दुनिया की फार्मेसी' संबंधी भारत की भूमिका मजबूत होगी। साथ ही चश्मे पर जीएसटी कम करने से चश्मा सुलभता से उपलब्ध होगा, क्योंकि लगभग 10 करोड़ लोगों को समुचित चश्मे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

करते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू किया। पहले वैट और कई तरह के टैक्स की जटिल प्रणाली थी, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था धीमी और बंटी हुई थी और इंटर-स्टेट टोल बूथ पर लंबी लाइनें लगती थीं। अब इसकी जगह एक ऐसा एकीकृत मार्केट आ गया है, जिसने अर्थव्यवस्था में निष्पक्षता, सरलता और मजबूती लाई है। केवल आठ वर्षों में ही जीएसटी टैक्सपेयर बेस 2017 के 66 लाख से बढ़कर आज 1.5 करोड़ से अधिक हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सालाना संग्रह 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। जीएसटी संग्रह अब प्रत्येक महीने 1.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो इस ऐतिहासिक सुधार के लागू होने के समय से कहीं अधिक है। डेलॉइट के एक सर्वे से पता चलता है कि 85% बिजनेस, जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं, जीएसटी से संतुष्ट हैं, जो यह साबित करता है कि भारत इस ऐतिहासिक यात्रा में व्यापारियों और उपभोक्ताओं को साथ लेकर अधिक आधुनिक हो सकता है।

सुधारों के अगले चरण में जीएसटी प्रणाली को और सरल बनाया गया है। इसमें आम जनता को केंद्र में रखा गया है। खाद्य पदार्थ और दवाओं जैसी जरूरी चीजों एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें काफी कम कर दी गई हैं। साथ ही, टैक्स की खामियों को ठीक किया जा रहा है। छोटे व्यवसायों, निर्यातकों और स्टार्टअप के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है। यह सुधार केंद्र सरकार के 'नागरिक

रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने से मध्यम वर्ग के साथ हर चेहरे पर मुस्कान

आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और इससे घरेलू बजट का बोझ कम होगा। दरों में कमी से आम उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उत्पादन को भी मिलेगा बढ़ावा...

- बहुत अधिक तापमान वाला (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर, चपाती और पराठा अब जीएसटी मुक्त, पहले 5% थी दर।
- टूथब्रश, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन, टॉयलेट सोप पर अब 5 फीसदी जीएसटी।
- टूथ पाउडर, कैंडल, फीडिंग बोतल, कपड़े का बैग, छाता, सिलाई मशीन, साइकिल, बांस से बने फर्नीचर, कंघी, हेयरपिन, डाइपर, पीने के पानी की 20 लीटर वाली बोतल, सोलर वाटर हीटर समेत घरेलू उपयोग की अधिकतर वस्तुओं पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी।
- एयर कंडीशनर, डिश वाशिंग मशीन, प्रोजेक्टर, सेट टॉप बॉक्स, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल 28% की बजाय 18% जीएसटी दर के दायरे में।

सिरका, संरक्षित टमाटर व मशरूम, फ्रोजन सब्जियां, सब्जियां-फल-मेवे-फलों के छिलके या पौधों के अन्य हिस्से जो चीनी में संरक्षित हों, जैम, फ्रूट जैली पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई।

1,000 रुपये तक के फुटवियर की जगह अब 2,500 रुपये तक की कीमत वाले फुटवियर पर 5 फीसदी जीएसटी। 2,500 रुपये से अधिक कीमत पर वर्तमान दर ही लागू रहेगी।

किचन के सामान पर लगने वाले 12% जीएसटी को अब 5% किया गया। वहीं, चॉकलेट पर पहले 18% की जगह अब यह दर 5% होगी।

> जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसने करों की संख्या, अनुपालन बोझ और आम आदमी पर समग्र कर बोझ में कमी की है जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और कर संग्रह में काफी वृद्धि हुई है।
>
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

देवो भवः' के लक्ष्य को दर्शाते हैं। जिसका उद्देश्य नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाना, व्यापारियों को सशक्त बनाना और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ाना है।

केंद्र सरकार केवल कागजों पर सुधार को सीमित नहीं रख रही, बल्कि यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि छूट और रियायतें सीधे उपभोक्ता तक पहुंचे। हर बचत और हर राहत को उपभोक्ता तक पहुंचाकर केंद्र सरकार दुकानदार और ग्राहक, व्यापारी और नागरिक के बीच विश्वास को मजबूत करने में जुटी है।

सुधारों के पंचरत्न

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ही अगर जीएसटी में हुए इस सुधार को संक्षिप्त रूप में समझें तो इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं।

पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सहज हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, खपत और वृद्धि दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। पांचवां, विकसित भारत के लिए को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्य एवं केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। इन सुधारों को समझने के लिए अतीत के पन्नों को पलटना भी जरूरी है। एक समय था, जब देश में बड़ी मात्रा में टैक्स देना पड़ता था। रसोई का सामान हो या खेती-किसानी से जुड़ी चीजें हों या फिर दवाइयां और यहां तक कि जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर अलग-अलग टैक्स देना पड़ता था। टूथपेस्ट, साबुन, तेल आदि पर 31 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता था। खाने की प्लेट, चम्मच आदि पर 18 से 28 प्रतिशत, बच्चों की टॉफी पर 21 प्रतिशत, साइकिल पर 17 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था। इलाज और जांच में 16 प्रतिशत, घूमने-फिरने, होटल बुकिंग पर भी अत्यधिक टैक्स अदा करना पड़ता था। घर के लिए टीवी, एसी आदि खरीदने में भी 31 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता था। किसानों के लिए जरूरी उपकरण भी 12-14 प्रतिशत के टैक्स के दायरे में थे लेकिन अब वह अतीत के पन्नों में ही सिमटा दी गई है। केंद्र सरकार ने 2014 के बाद जिस तरह से सुधारों का सिलसिला शुरू किया और उसे निरंतरता में जारी रखा है, उससे नागरिकों का जीवन आसान हो गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, छोटे व्यापारी-कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है। साथ ही, कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी।

टीम भारत का अप्रतिम उदाहरण

जीएसटी का आधारभूत विचार मौलिक नहीं था। दुनिया के कई देशों में प्रयोग के तौर पर इसे लागू किया जा चुका है। अनेक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मॉडल को विकसित करना जरूरी था। भारत राज्यों का एक ऐसा संघ है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही राजकोषीय अथवा वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ होना अत्यंत जरूरी है। भारत राज्यों का परिसंघ नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार के राजस्व की कीमत पर राज्यों की राजस्व स्थिति को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता है। ऐसे में देश के बाजारों को एक सूत्र में बांधने की आधारशिला वर्ष 2000 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। भारत की विविधता और उसकी जटिलता के लिए पूरी तरह से उपयुक्त जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया।

फिर वर्ष 2006 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रस्तावित किया कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू किया

क्रिसिल इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी की दरों में कटौती के कारण इस वित्त वर्ष भारतीय कंपनियों का राजस्व 6-7% बढ़ने की संभावना है। इस कटौती से जहां दोपहिया वाहनों की बिक्री में 5 से 6% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, वहीं घरों की निर्माण लागत में 3.5-4.5% की कमी आने की उम्मीद है।

देश की जीडीपी 330 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 202 लाख करोड़ रुपये खपत है। **GST** छूट के बाद यदि खपत 10% बढ़ती है, तो अतिरिक्त 20 लाख करोड़ रुपये की खपत बढ़ेगी, जिससे उत्पादन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां सक्रिय होंगी।

> जीएसटी लागू होना भी देश की आर्थिक स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण कदम है। 70 वर्ष में जो व्यवस्था बन गई थी, कारोबार करने में जो कमियां थीं, जो मजबूरियां थीं, उन्हें पीछे छोड़कर देश अब आगे बढ़ चला है। जीएसटी से भी देश में पारदर्शिता का एक नया अध्याय शुरू हुआ है।
>
> \- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

उद्योग, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता आसान हुआ

विकास की रफ्तार अब और तेज

जीएसटी 2.0 के तहत केवल 2 कर स्लैब व्यापार को आसान बनाएंगे तो इससे इनपुट लागत में भी कमी आएगी। कीमतें घटने से मांग में बढ़ोतरी सिर्फ घरेलू उत्पादन को ही नहीं, मेड इन इंडिया को भी देगी बढ़ावा...

एमएसएमई की राह आसान

- पंजीकरण व रिटर्न फाइलिंग हुई सरल, रिफंड में तेजी लाई गई है।
- अनुपालन लागत कम की गई है, जिससे व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप पर बोझ कम हो गया है।

घर बनाना हुआ सस्ता

सीमेंट पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% हुई। संगमरमर/ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, रेत-चूना ईंटें, बांस फर्श/जॉइनरी, पैकिंग मामलों और पैलेट (लकड़ी) पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई।

- फायदा : घर और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की लागत कम होगी, जिससे घर खरीदना अधिक किफायती हो जाएगा। रियल एस्टेट में मांग बढ़ेगी तो नए रोजगार सृजित होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम घटे

- सभी तरह की एलसीडी/एलईडी टेलिविजन और मॉनिटर पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई।

- फायदा : भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी, वहीं उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं पर कम पैसे खर्च करने होंगे।

जाएगा लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। नवंबर 2009 में पहला चर्चा पत्र जारी किया गया, जिसमें जीएसटी की विशेषताओं के बारे में बताया गया। मार्च 2011 में इसका बिल पेश किया गया लेकिन राजनैतिक सहमति नहीं बन पाई और 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही बिल भी खत्म हो गया। वर्ष 2014 में केंद्र में नई सरकार के सत्ता में आने पर इस प्रक्रिया को तेज किया गया। दिसंबर 2014 में बिल पेश हुआ और मई 2015 में लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का निर्णय हुआ। कमेटी ने 22 जुलाई 2015 को अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद राजनीतिक सहमति के साथ 1 अगस्त 2016 को संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को और फिर 8 अगस्त 2016 को लोकसभा ने इसे पारित किया। आधे से अधिक राज्यों की सहमति की औपचारिक प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को इसे अधिसूचित किया। इसके साथ ही भारत में जीएसटी का मार्ग प्रशस्त हुआ। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे भारत के लिए विजन दिया जो देश के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक साथ काम करता हो। आज जीएसटी की सबसे बड़ी सफलता यह है कि जीएसटी परिषद एक अत्यंत कारगर एवं प्रभावशाली निर्णय निर्माता संघीय संस्था साबित हुई है। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने संघीय गवर्नेंस के मामले में इतिहास रच दिया।

ऑटोमोबाइल सेक्टर पकड़ेगा नई रफ्तार

- छोटी कार, दोपहिया वाहन और उनकी साइड कार पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई। बस, ट्रक, तिपहिया, सभी ऑटो पार्ट्स भी 28% की जगह 18% जीएसटी स्लैब में होंगे।
- ड्राइवर समेत 10 या उससे अधिक यात्रियों की क्षमता वाले बायो-फ्यूल पर चलने वाले वाहन, 1200 सीसी तक के सीएनजी या एलपीजी वाहन, 4,000 एमएम तक लंबाई वाले 1,500 सीसी तक के डीजल वाहन और माल वाहन पर लगने वाला 28% जीएसटी दर को घटाकर 18% किया गया।
- बाइक के पार्ट, गाड़ियों की सीट और चप्पू वाली नाव पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% की गई।

- फायदा : सभी तरह के ऑटो पार्ट पर एक समान 18 फीसदी जीएसटी किया गया, इससे वर्गीकरण से जुड़े विवाद खत्म होंगे। छोटी कार और बाइक पर जीएसटी घटने से मध्यम वर्ग को फायदा तो मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिला। कई कंपनियों ने कार की कीमत कम करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में वाहनों की कीमत 70-75 हजार रुपये से लेकर 2 से 2.25 लाख रुपये तक कम होने की संभावना है। ऑटो इंडस्ट्री प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है।

खिलौना और हस्तशिल्प सस्ता

हस्तशिल्प की मूर्तियों, प्रतिमाओं, पेंटिंग, लकड़ी/धातु/कपड़ा गुड़िया, खिलौनों, हैंडमेड पेपर, पेपर बोर्ड, मैन मेड सिलाई धागा और सूत पर अब जीएसटी दर 12% से घटकर 5% होगी। वहीं, इंवर्टेड शुल्क संरचना को मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित यार्न पर 12% से घटाकर 5% करने के साथ ठीक किया गया है। देश की टॉय इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा और सस्ते विदेशी खिलौनों के मुकाबले स्थानीय उत्पादकों की बिक्री बढ़ेगी।

- फायदा : मानव निर्मित फाइबर धागा के लिए शुल्क ढांचा तय करने से वस्त्र उद्योग स्पर्धात्मकता और विशेषतौर पर निर्यात में सुधार होगा। कारीगरों की आजीविका में सहायता मिलेगी, भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण के साथ ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

आतिथ्य क्षेत्र में बढ़ेगी मांग, जिम-सैलून भी सस्ता

7,500 रुपये प्रति दिन किराए वाले होटल के कमरे पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई। जिम, सैलून, नाई, योग पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% की गई। 100 रुपये या उससे कम शुल्क वाले सिनेमा टिकट पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई।

- फायदा : उपलब्धता बढ़ेगी और आतिथ्य तथा वेलनेस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

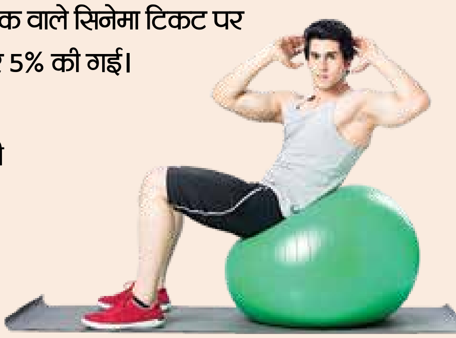

पूर्व में जीएसटी मॉडल राजस्व केंद्रित था। तब एकल कर प्रणाली को अपनाने की दिशा में कदम उठाते हुए राज्यों से सीएसटी को समाप्त करने के लिए कहा गया था। राज्यों से वादा किया गया था कि सीएसटी को समाप्त करने के बदले में कुछ वर्षों तक उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। राज्यों ने तदनुसार ऐसा ही किया, लेकिन सीएसटी के बदले में मुआवजा देने का वादा पूरा नहीं हुआ। जब मई 2014 में अरुण जेटली ने केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला, तब सभी राज्यों ने उनसे कहा कि जीएसटी पर तभी चर्चा होगी जब सीएसटी से जुड़ा पिछला मुआवजा मिलेगा। नई सरकार ने राज्य सरकारों का भरोसा हासिल करते हुए तत्काल मुआवजा अदा किया और इसके साथ ही जीएसटी पर बात आगे बढ़ने लगी।

दूसरा कारण यह था कि राज्यों के मन में यह संशय था कि जीएसटी को पूरी तरह से लागू करने के दौरान उन्हें राजस्व का नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल यह था कि राज्यों को नुकसान की भरपाई किस तरह से की जाएगी। उनकी मांग जायज प्रतीत होती थी, इसका हल पहले नहीं निकाला गया। विशेषकर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विनिर्माण वाले राज्य इसको लेकर काफी चिंतित थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 'मुआवजा नहीं तो जीएसटी नहीं'। ऐसे में 2014 के बाद नई केंद्र सरकार ने जीएसटी परिषद में विचार-विमर्श करने के बाद राज्यों को कुछ भी राजस्व

जीएसटी 1.0 से 2.0 तक...

आपके मन के हर सवाल का जवाब

एक राष्ट्र-एक कर की अवधारणा के साथ 1 जुलाई 2017 को देश के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में लागू किए गए जीएसटी ने 8 सालों में देश के आर्थिक विकास को एक नई दिशा दी है। इंस्पेक्टर और परमिट राज के खात्मे से लेकर पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू करने तक यह मील का पत्थर साबित हुआ है। 8 साल पहले हुई शुरुआत और अब उसमें सुधार को लेकर कई ऐसे प्रश्न हैं, जो आपके दिमाग में कई बार उमड़ते होंगे। यहां पढ़िए आपके हर सवाल का जवाब...

Q क्या जीएसटी सिर्फ एक टैक्स बोझ है?

A बिलकुल नहीं! जीएसटी ने 17 अलग-अलग केंद्र और राज्य करों व 13 उपकरों को हटाकर एक सरल कर प्रणाली लागू की है, जिससे टैक्स बोझ कम होगा।

Q अब एक और 'सुधार' क्यों? क्या जीएसटी ने पहले ही सब कुछ ठीक नहीं कर दिया था?

A 2017 में पहला कदम था। अब जीएसटी 2.0 में टैक्स स्लैब घटाकर मुख्य रूप से 2 कर दिए गए हैं 5% और 18%। जिससे यह और भी आसान और अनुपालन के अनुकूल हो गया है।

Q तो अब अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार यानी **Next Gen GST Reforms** की बात क्यों हो रही है?

A 8 साल पहले **GST** लागू हुआ था। आज, जीएसटी प्रणाली स्थिर हो गई है और 2024 से हर महीने लगभग 1.8 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हो रहा है। यह अब अगले बदलाव के लिए तैयार है।

Q क्या इसका मतलब यह है कि जीएसटी 1.0 विफल रहा?

A बिलकुल नहीं। जीएसटी 1.0 ने भारत की कर प्रणाली को एकीकृत किया। जीएसटी 2.0 उसी आधार पर इसे और अधिक स्वच्छ, सरल और पारदर्शी बनाता है।

Q क्या छोटे व्यापारी अब भी कई स्लैब या बदलाव से कन्फ्यूज रहेंगे?

A अब जीएसटी 2.0 में कम स्लैब होने से वह कन्फ्यूजन खत्म हो गई है। स्पष्ट टैक्स रेट से व्यापार करना आसान और सुचारु होगा।

नुकसान होने पर प्रथम पांच वर्षों तक राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि करने पर सहमति दे दी। राज्यों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस तरह जीएसटी लागू करने के लिए राज्यों का भरोसा जीतने में सफल हो गए। आम सहमति सुनिश्चित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, ताकि सर्वसम्मति से जीएसटी को लागू किया जा सके। जीएसटी से जुड़े सभी विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गए। जीएसटी परिषद के समक्ष संबंधित नियम-कायदे पेश किये गए। उन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी नए एवं डिजिटल भारत की कर व्यवस्था है। यह केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, बल्कि वे ऑफ डूइंग बिजनेस को भी एक दिशा दे रहा है। यह केवल एक कर सुधार नहीं है, बल्कि आर्थिक सुधार का भी महत्वपूर्ण कदम है। यह आर्थिक सुधार से भी आगे सामाजिक सुधार का भी एक नया तबका तैयार कर रहा है जो एक ईमानदारी के उत्सव की ओर ले जाने वाला बना है। इसी दिशा में जीएसटी 2.0 के रूप में परिवर्तनकारी सुधार विकसित भारत का मार्ग तेजी से प्रशस्त करने वाला कदम बन गया है। इन सुधारों के पीछे एक बड़ी सोच है- ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आज महंगाई की दर भी, बहुत निचले स्तर पर है, नियंत्रण में है और यही जनहितैषी सुशासन की पहचान है। जब जनहित और राष्ट्र हित में फैसले लिए जाते हैं, तब देश आगे बढ़ता है और इसलिए ही आज

Q नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों में बड़ा बदलाव क्या है? इससे क्या फर्क पड़ेगा?

A पहले 4 टैक्स स्लैब थे, अब सिर्फ मुख्य रूप से 2 रह गए हैं। पहला 5%, जिसमें जरूरी सामान है। वहीं, 18%, जिसमें ज्यादातर सामान और सेवाएं हैं। पुराने सिस्टम में लागू 28% स्लैब का ज्यादातर सामान अब 18% स्लैब में आ गया है। जैसे कारें, एसी, टीवी मतलब इन सबके दाम अब 10% या उससे ज्यादा घट गए हैं।

Q पहले कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स और तैयार सामान पर कम टैक्स क्यों लगता था?

A अब ऐसा नहीं होगा। जीएसटी 2.0 में इनवर्टेड ड्यूटी की समस्या कम कर दी गई है। रिफंड आसानी से मिलेगा और कारोबारियों का पैसा नहीं फंसेगा।

Q क्या जीएसटी 2.0 में एमएसएमई पर अब भी अनुपालन का बोझ रहेगा?

A नहीं! **AI** से बने प्री-फिल्ड रिटर्न, तुरंत रिफंड, वन-क्लिक रजिस्ट्रेशन से जीएसटी 2.0 ने एमएसएमई सेक्टर के लिए अनुपालन को तेज, आसान और स्मार्ट बनाया है।

Q टैक्स रेट घटाए जाने से क्या राज्यों को नुकसान होगा?

A नहीं। 12% वाले स्लैब से वैसे भी बहुत कम राजस्व आता था। 28% वाले सामान को 18% में लाने से मांग बढ़ेगी। चुनिंदा विलासिता के सामान और सेवाओं पर 40% टैक्स से राज्यों की कमाई मजबूत होगी।

Q व्यापारियों के लिए तो ठीक है लेकिन मेरे लिए क्या? क्या मेरे रोजमर्रा के खर्च सच में कम होंगे?

A हां! किराने का सामान, दवाइयां अब सरल स्लैब में आ गए हैं। जरूरी चीजें 0 या 5% पर रहेंगी और ज्यादातर सेवाएं 18% स्लैब में हैं।

Q क्या सभी कृषि मशीनरी/उपकरणों पर जीएसटी कम कर दिया गया है?

A स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, मिट्टी तैयार करने या खेती के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, लॉन या खेल के मैदान में रोलर, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर शामिल हैं। घास या घास काटने की मशीन, अन्य कृषि, बागवानी, वानिकी, मुर्गी पालन या मधुमक्खी पालन मशीनरी, कम्पोस्ट मशीन आदि पर जीएसटी दर पहले 12% थी। अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है।

Q कृषि मशीनरी को पूर्ण छूट क्यों नहीं दी गई है?

A दर सरलीकरण का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और उत्पादकों के बीच संतुलन बनाए रखना है। किसानों को राहत प्रदान करते समय यह महत्वपूर्ण है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यदि कृषि मशीनरी को पूर्ण छूट दी जाती है, तो इन वस्तुओं के निर्माता/विक्रेता कच्चे माल पर भुगतान किए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगे और उन्हें इनपुट पर भुगतान किए गए आईटीसी को वापस करना होगा। इससे उनके प्रभावी कर भार और उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। इसका परिणाम यह होगा कि इसका बोझ किसानों पर अधिक कीमतों के रूप में पड़ेगा, जिससे यह उपाय प्रतिकूल हो जाएगा।

भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत है। यानी दुनिया में भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह 140 करोड़ भारतीयों का सामर्थ्य और संकल्प है। इसलिए भारत ने जीएसटी 2.0 यानी नए सुधारों से पुनः संकल्प लिया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सुधारों का यह सिलसिला चलता रहेगा।

निश्चित रूप से यह सुधार भारत को समान कर प्रणाली के एक सूत्र में बांधने वाला कदम बना, जिससे देश में कारोबारी गतिविधियां बढ़ी, देश की जीडीपी को भी नया रूप मिला और महंगाई को काबू करने में भी सफलता मिली। इसी का परिणाम है कि छोटे हो या बड़े व्यापारी, आज सहजता से व्यापार कर रहे हैं और एक टैक्स प्रणाली से रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था सहज और सुगम हो गई है। जीएसटी की सफलता यह सिद्ध करती है कि पुराना भारत आर्थिक दृष्टि से खंडित था, नया भारत एक देश के लिए एक कर, एक बाजार बना है। एक ऐसा भारत बना है, जहां केंद्र और राज्य साझी समृद्धि के समान लक्ष्य के लिए एक साथ सहयोगी एवं सद्भावपूर्ण भाव से काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार यानी जीएसटी 2.0 से नया भारत नई नियति लिखने को तैयार है। ■

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जीएसटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए **QR** कोड स्कैन करें।

तमिलनाडु की माटी से कर्तव्य पथ तक
उपराष्ट्रपति बने सी.पी. राधाकृष्णन

संविधान की भावना के अनुरूप 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तमिलनाडु मूल के चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 12 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें इस संवैधानिक पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही देश को औपचारिक रूप से लोकतंत्र यानी विशेष रूप से संसद के उच्च सदन को मिल गया है नया मार्गदर्शक...

उनका सार्वजनिक जीवन समाज की जड़ों से प्रारंभ होकर निष्ठा, कर्मठता और प्रशासनिक दक्षता से परिपूर्ण रहा है। तमिलनाडु की पावन मिट्टी में पले-बढ़े और उपराष्ट्रपति के रूप में संसद के उच्च सदन के सभापति के गरिमामयी आसन पर आसीन होने वाले चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जनसेवा से शिखर तक की यात्रा की है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने अनुभव, समर्पण और सेवा का सम्मान करते हुए सी.पी. राधाकृष्णन को न केवल उम्मीदवार बनाया, बल्कि उनकी जीत भी सुनिश्चित की। राधाकृष्णन ने 12 सितंबर को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही अनुभव और मर्यादा के संगम राधाकृष्णन के नेतृत्व में संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा और भी सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके उपराष्ट्रपति चुने जाने पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, "थिरु सी.पी. राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। वे एक ऐसे

उपराष्ट्रपति चुनाव का वोट समीकरण

- उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 9 सितंबर को मतदान हुआ और परिणाम भी घोषित हुआ।
- इस चुनाव में राज्यसभा के कुल 245 और लोकसभा के 543 सदस्य वोटर थे (कुल 788) जिसमें राज्यसभा में छह और लोकसभा में एक सीट खाली होने की वजह से प्रभावी वोट की संख्या 781 थी।
- हालांकि कुल 767 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से 752 वोट वैध पाए गए जबकि 15 वोट को अमान्य घोषित किया गया।
- इस चुनाव में 98.2 प्रतिशत वोटिंग हुई। सत्ता पक्ष की ओर से उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 और विपक्ष के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले।

सी.पी. राधाकृष्णन जी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहा। एक समर्पित लोक सेवक के रूप में, उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित कर दिया। जनता की सेवा के लिए समर्पित, उनके सफल उपराष्ट्रपति कार्यकाल की कामना करता हूं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा

सी.पी. राधाकृष्णन का संक्षिप्त परिचय

- पूरा नाम : चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, उम्र 68 वर्ष
- जन्म : 4 मई 1957, जिला तिरुपुर, तमिलनाडु
- पेशा : किसान और उद्योगपति
- छात्र राजनीति से राजनीतिक जीवन की शुरुआत। 16 साल की उम्र में ही वर्ष 1974 में जनसंघ से जुड़ गए थे।
- 1996 में राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के सचिव बने।
- 1998 में वे पहली बार कोयंबटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वे पुनः कोयंबटूर लोकसभा के लिए चुने गए।
- 2004 में प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। वे ताइवान जाने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे।
- 2004 से 2007 के बीच तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान 93 दिनों तक उन्होंने 19,000 किलोमीटर की 'रथ यात्रा' की।
- यह यात्रा सभी नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू, अस्पृश्यता निवारण और नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने जैसी मांगों को उजागर करने के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने दो और पद यात्राओं का नेतृत्व भी किया।
- वर्ष 2016 से वर्ष 2020 के बीच कॉयर बोर्ड के चेयरमैन रहे, बतौर चेयरमैन रहते भारत के कॉयर सेक्टर से 2,532 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निर्यात हुआ।
- तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रहे।
- झारखंड के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा किया। साथ ही झारखंड, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में ट्यूबरक्लोसिस बीमारी समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए।
- एक उत्साही खिलाड़ी रहे हैं और कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस में चैंपियन एवं लंबी दूरी के धावक भी थे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है।
- उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, तुर्की, चीन, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जापान की यात्रा की है।

व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और गरीबों व वंचितों के सशक्तीकरण के लिए समर्पित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को बेहतर बनाएंगे।" उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद सी.पी.राधाकृष्णन ने भी मीडिया से कहा कि नई जिम्मेदारी में वह देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। चुनाव खत्म हो गया है और हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब विकास के काम पर सबको फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों पक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं ऐसे में लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करना है।

अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में सी.पी. राधाकृष्णन ने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से विशिष्ट पहचान बनाई है। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने सदैव सामुदायिक सेवा और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। उन्हें सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव प्राप्त है। संसदीय मामलों में उनके हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे हैं। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने आम नागरिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान पर ध्यान दिया। ■

उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

भूपेन दा...

भारत के रत्न

भारत रत्न से सम्मानित डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जन्म जयंती देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावपूर्ण लेख के माध्यम से उनकी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक योगदान को याद कर भूपेन दा को नमन किया। आधुनिक असम की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ने और वैश्विक पहचान देने वाले भूपेन हजारिका सदैव भारतीय संस्कृति और संगीत जगत में अविस्मरणीय योगदान के लिए स्मरणीय हैं। पेश है प्रधानमंत्री मोदी का आलेख...

जन्म- 8 सितंबर 1926 | निधन- 5 नवंबर 2011

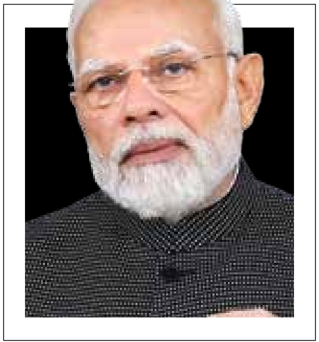

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

भूपेन दा की जीवन यात्रा में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। उनकी रचनाओं ने भाषा और क्षेत्र की सीमाएं तोड़कर एकजुट किया।

भारतीय संस्कृति और संगीत से लगाव रखने वालों के लिए आज 8 सितंबर का दिन बहुत खास है। और विशेषकर इस दिन के साथ असम के मेरे भाइयों और बहनों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आज भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म जयंती है। वे भारत की सबसे असाधारण और सबसे भावुक आवाज़ों में से एक थे। ये बहुत सुखद है कि इस वर्ष उनके जन्म शताब्दी वर्ष का आरंभ हो रहा है। यह भारतीय कला-जगत और जन-चेतना की दिशा में उनके महान योगदानों को फिर से याद करने का समय है।

भूपेन दा ने हमें संगीत से कहीं अधिक दिया। उनके संगीत में ऐसी भावनाएं थीं जो धुन से भी आगे जाती थीं। वे केवल एक गायक नहीं थे, वे लोगों की धड़कन थे। कई पीढ़ियां उनके गीत सुनते हुए बड़ी हुईं। उनके गीतों में करुणा, सामाजिक न्याय, एकता और गहरी आत्मीयता की गूंज है। भूपेन दा के रूप में असम से एक ऐसी आवाज़ निकली जो किसी कालजयी नदी की तरह बहती रही। भूपेन दा सशरीर हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है। वो आवाज आज भी सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। उसमें मानवता का स्पर्श है। भूपेन दा ने दुनिया का भ्रमण किया, समाज के हर वर्ग के लोगों से मिले, लेकिन वे असम में अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। असम की समृद्ध मौखिक परंपराएं, लोकधुनें और सामुदायिक कहानी कहने के तरीकों ने उनके बचपन को गढ़ा। यही अनुभव उनकी कलात्मक भाषा की नींव बने। वे असम की आदिवासी पहचान और लोगों के सरोकार को हर समय साथ लेकर चले।

बहुत छोटी उम्र से उनकी प्रतिभा लोगों को नजर आने लगी। केवल पांच वर्ष की उम्र में उन्होंने सार्वजनिक मंच पर गाया। वहां लक्ष्मीनाथ बेझबरुआ जैसे असमिया साहित्य के अग्रदूत ने उनके कौशल को पहचाना। किशोरावस्था तक पहुंचते-पहुंचते उन्होंने अपना पहला गीत रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन संगीत उनके व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू था। भूपेन दा भीतर से एक बौद्धिक व्यक्तित्व थे। जिज्ञासु, साफ बोलने वाले, दुनिया को समझने की अटूट चाह रखने वाले। ज्योति प्रसाद अग्रवाला और विष्णु प्रसाद रभा जैसे सांस्कृतिक दिग्गजों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला, और उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया।

सीखने की यही लगन उन्हें कॉटन कॉलेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तक ले गई। वो बीएचयू में राजनीति शास्त्र के छात्र थे, लेकिन उनका अधिकतर समय संगीत साधना में बीतता था। बनारस ने उन्हें पूरी तरह संगीत की तरफ मोड़ दिया। काशी का सांसद होने के नाते मैं उनकी जीवन यात्रा से एक जुड़ाव महसूस करता हूं, और मुझे बहुत गर्व होता है।

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का प्रतिबिंब भूपेन दा का जीवन

भूपेन हजारिका की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, तो 13 सितंबर को गुवाहाटी में उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। भूपेन दा के अमूल्य योगदान का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भूपेन हजारिका को प्यार से 'शुधा कॉन्ठो' कहते थे। यह उन 'शुधा कॉन्ठो' का जन्म शताब्दी वर्ष है जिन्होंने भारत की भावनाओं को आवाज दी। जिन्होंने संगीत को संवेदना से जोड़ा और संगीत में भारत के सपनों को संजोया। जिन्होंने मां गंगा से मां भारती की करुणा को कह सुनाया। भूपेन दा ने गंगा बहती हो क्यों जैसी कई अमर रचनाएं रची जो अपने स्वरों से भारत को जोड़ती रही और भारत की पीढ़ियों को झकझोरती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम उनके गीतों में मां भारती के लिए इतना प्रेम इसलिए देखते हैं क्योंकि वो एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को जीते थे। हमारी सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न देकर, पूर्वोत्तर के सपनों और स्वाभिमान का सम्मान किया। भूपेन दा, भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। गुवाहाटी में आयोजित जन्म शताब्दी समारोह यह प्रेरणा दे रही है कि भले भूपेन दा शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गीत और उनकी आवाज आज भी भारत की विकास यात्रा के साक्षी हैं। यह समारोह भूपेन दा के जीवन और उनकी विरासत को सम्मानित करता है, जिनका असमिया संगीत, साहित्य और संस्कृति में योगादन अद्वितीय है।

काशी से आगे बढ़ी जीवन यात्रा में फिर उन्होंने अमेरिका में कुछ समय बिताया। वहां उन्होंने अपने समय के नामचीन विद्वानों, विचारकों और संगीतकारों से संवाद किया। वे पॉल रोबसन से मिले, जो दिग्गज कलाकार और सिविल राइट्स नेता थे। रोबसन का गीत "Ol' Man River" उनके कालजयी गीत 'बिश्टीरनो परोरे' की प्रेरणा बना। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला एलेनॉर रूजवेल्ट ने भारतीय लोकसंगीत प्रस्तुतियों के लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी दिया।

भूपेन हजारिका, संगीत के साथ ही मां भारती के भी सच्चे उपासक थे। भूपेन दा के पास अमेरिका में रहने का विकल्प था, लेकिन वे भारत लौट आए और संगीत साधना में डूब गए। रेडियो से लेकर रंगमंच तक, फिल्मों से लेकर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री तक, हर माध्यम में वे पारंगत थे। जहां भी गए, नई प्रतिभाओं को समर्थन दिया।

भूपेन दा की रचनाएं काव्यात्मक सौंदर्य से भरी रहीं और साथ-साथ उन्होंने सामाजिक संदेश भी दिए। गरीबों को न्याय, ग्रामीण विकास, आम नागरिक की ताकत, ऐसे अनेक विषय उन्होंने उठाए। उनके गीतों ने नाविकों, चाय बागान के मजदूरों, महिलाओं, किसानों की आकांक्षाओं को आवाज दी। उनकी रचनाएं लोगों को पुरानी स्मृतियों में ले जाती थीं, साथ ही, उन्होंने आधुनिकता को देखने का एक सशक्त नजरिया भी दिया। बहुत से लोग, खासकर सामाजिक रूप से वंचित तबकों के लोग, उनके संगीत से शक्ति और आशा पाते रहे... और आज भी पा रहे हैं।

भूपेन दा की जीवन यात्रा में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। उनकी रचनाओं ने भाषा और क्षेत्र की सीमाएं तोड़कर एकजुट किया। उन्होंने असमिया, बांग्ला और हिन्दी फिल्मों के लिए संगीत रचा। उनकी आवाज में जो पीड़ा थी, वो बरबस हम सभी का ध्यान खींच लेती थी। 'दिल हूम हूम करे' में जो पीड़ा बहती है, वो सीधे दिल की गहराइयों को छू लेती है। और जब वे पूछते हैं, 'गंगा बहती है क्यूं', तो ऐसा लगता है मानो हर आत्मा को झकझोर कर जवाब मांग रहे हों।

उन्होंने पूरे भारत के सामने असम को सुनाया, दिखाया, महसूस कराया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आधुनिक असम की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ने में उनका बड़ा योगदान रहा। असम के भीतर और दुनिया भर के असमिया प्रवासियों, दोनों के लिए वो असम की आवाज बने। भूपेन दा राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी जनसेवा की दुनिया से जुड़े रहे। 1967 में वे असम के नौबोइचा से निर्दलीय विधायक चुने गए। यह दिखाता है कि लोगों को उन पर कितना गहरा विश्वास था। उन्होंने राजनीति को अपना करियर नहीं बनाया, लेकिन हमेशा लोगों की सेवा में जुटे रहे। भारत की जनता और भारत सरकार ने उनके योगदान का सम्मान किया। उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण, दादासाहेब फाल्के अवार्ड समेत कई सम्मान मिले। 2019 में हमारे कार्यकाल के दौरान उन्हें भारत रत्न मिला। यह मेरे लिए और एनडीए सरकार के लिए भी सम्मान की बात थी। दुनिया भर में, खासकर असम और उत्तर-पूर्व के लोगों ने, इस अवसर पर खुशी जताई। यह उन सिद्धांतों का सम्मान था, जिन्हें भूपेन दा दिल से मानते थे। वो कहते थे कि सच्चाई से निकला संगीत किसी एक दायरे में सिमट कर नहीं रहता। एक गीत लोगों के सपनों को पंख लगा सकता है, और दुनिया भर के दिलों को छू सकता है।

मुझे 2011 का वह समय याद है जब भूपेन दा का निधन हुआ। मैंने टीवी पर देखा, उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग पहुंचे। हर आंख नम थी। जीवन की तरह, मृत्यु में भी उन्होंने लोगों को साथ ला दिया। इसलिए उन्हें जलुकबाड़ी की पहाड़ी पर ब्रह्मपुत्र की ओर देखते हुए अंतिम विदाई दी गई, वही नदी जो उनके संगीत, उनके प्रतीकों और उनकी स्मृतियों की जीवनरेखा रही है। अब ये देखना बहुत सुखद है कि असम सरकार भूपेन हजारिका कल्चरल ट्रस्ट के कार्यों को बढ़ावा दे रही है। यह ट्रस्ट युवा पीढ़ी को भूपेन दा की जीवन यात्रा से जोड़ने में जुटा है।

भूपेन दा की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के लिए देश के सबसे बड़े पुल को भूपेन हजारिका सेतु नाम दिया गया। 2017 में जब मुझे इस सेतु के उद्घाटन का अवसर मिला, तो मैंने महसूस किया कि असम और अरुणाचल... इन दो राज्यों को जोड़ने वाले, उनके बीच की दूरी कम करने वाले इस सेतु के लिए भूपेन दा का नाम सबसे उपयुक्त है।

उनका जीवन हमें करुणा की शक्ति का एहसास कराता है। लोगों को सुनने और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की सीख देता है। उनके गीत आज भी बच्चों और बुजुर्गों, दोनों की जुबान पर हैं। उनका संगीत हमें माननीय और साहसी बनना सिखाता है। वह हमें अपनी नदियों, अपने मजदूरों, अपने चाय बागान के कामगारों, अपनी नारी शक्ति और अपनी युवा शक्ति को याद रखने को कहता है। वह हमें विविधता में एकता पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है।

भारत भूपेन हजारिका जैसे रत्न से धन्य है। जब हम उनके शताब्दी वर्ष का आरंभ कर रहे हैं, तो आइए यह संकल्प लें कि उनके संदेश को दूर-दूर तक पहुंचाएंगे। यह संकल्प हमें संगीत, कला और संस्कृति के लिए और काम करने की प्रेरणा दे, नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करे, भारत में सृजनात्मकता और कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा दे। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। ■

"मोहन भागवत जी हमेशा से 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के प्रबल समर्थक रहे हैं"

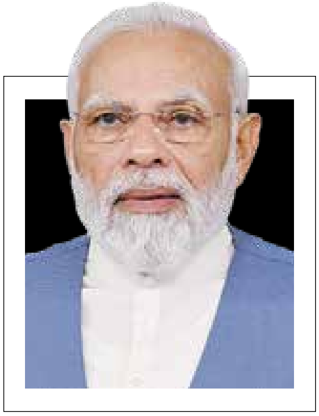

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

इस वर्ष 2 अक्टूबर एक विशेष संयोग लेकर आया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के साथ विजयादशमी का पावन त्योहार है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। यानी विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन है। लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की समर्पित यात्रा राष्ट्र की सेवा में गौरवमयी स्वर्णिम पृष्ठ है, जिसने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को बढ़ावा दिया है। संघ को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बताते हुए प्रधानमंत्री ने 100 साल की भव्य यात्रा को राष्ट्र के लिए प्रेरणा बताया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के जन्मदिन 11 सितंबर के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक विशेष ब्लॉग लिखकर सामाजिक योजनाओं- स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ को जन आंदोलन बनाने में संघ के स्वयंसेवकों के योगदान और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में समर्पण के भाव का किया जिक्र...

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्वबंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है।

संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं भागवत जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।

मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता, स्वर्गीय मधुकरराव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकरराव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकरराव जी जीवनभर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी। मधुकरराव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।

भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक

गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग कर पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं।

शब्द सुनकर ये भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते हैं उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग कर पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं।

भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे।

वर्ष 2000 में वे सरकार्यवाह बने। यहां भी भागवत जी ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला। 2009 में वे सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। भागवत जी ने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा।

सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है।

भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं, और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहनजी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वो गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए।

कोरोना काल में मोहन भागवत जी के प्रयास विशेष रूप से याद आते हैं। उस कठिन समय में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। उनके मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों तक हरसंभव सहायता पहुंचाई, जगह-जगह मेडिकल कैंप लगाए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों और वैश्विक विचार को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं को विकसित किया। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन भागवत जी की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी।

इस वर्ष की शुरुआत में, मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जी जुटे हुए हैं, वो हर किसी को प्रेरणा देता है।

समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर मोहन भागवत जी का विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्व बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुम्ब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। देश और समाज के लिए सोचने वाले हर भारतवासी को पंच परिवर्तन के इन सूत्रों से अवश्य प्रेरणा मिलेगी।

संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विज़न और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, मोहन जी इन दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं।

मोहन जी के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता ये है कि वो मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है। मोहन जी, हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं। भारत की विविधता और भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही अनेक संस्कृतियों और परंपराओं के उत्सव में भागवत जी पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ये पता है कि मोहन भागवत जी अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते है। वे विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण हैं। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है।

समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर मोहन भागवत जी का विशेष बल रहा है।

पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत जी ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। मोहन जी का बहुत जोर आत्मनिर्भर भारत पर भी है।

कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं।

यह भारत और विश्वभर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है।

मैं मां भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूं। उन्हें जन्मदिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं। ■

स्वच्छता से निकला संपन्नता का नया मार्ग

नागरिक जीवन में संपन्नता आती है खुशहाली से... और खुशहाल जीवन के लिए पहला पड़ाव होता है मूलभूत जरूरतों की पूर्ति। लगभग 11 वर्ष पूर्व देश की 60% आबादी शौचालय की सुविधा से भी वंचित थी। ऐसे में 2014 से देश में एक नई शुरुआत हुई और लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान एक जनआंदोलन बन गया। गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई एक साधारण सी दिखने वाली यह पहल आज केवल एक नहीं, बल्कि तीन-तीन स्तर (त्रिस्तरीय) के प्रभाव का प्रतीक बन गई है, जो केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पहले पड़ाव से आगे निकलकर स्वस्थ, सशक्त नागरिक जीवन के साथ-साथ बन गई है कचरे से कंचन बनाने वाली उद्यमिता, स्टार्टअप और आत्मनिर्भरता की मिसाल...

अकसर, ऐसा होता है कि किसी योजना का लाभ उद्देश्य की पूर्ति मात्र से ही पूर्ण हो जाता है फिर उस योजना की गति मंद पड़ जाती है या बंद हो जाती है लेकिन, यह निर्विवाद सत्य है कि जब किसी योजना की बागडोर नागरिक अपने हाथों ले लेते हैं तो उसका परिणाम वर्तमान पीढ़ी तक ही नहीं रहता, बल्कि सदियों तक अध्ययन का विषय बन जाती है। ऐसी ही एक योजना भारत के नागरिकों की गरिमामय जीवन के साथ-साथ संपन्नता की पथ-प्रदर्शक बन गई है। यह ऐसा अभियान बन गई है कि एक हजार साल बाद भी, जब 21वीं सदी के भारत का अध्ययन होगा, तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला, जन-आंदोलन है। अगर बीते 11 वर्ष के स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा को देखें तो सही अर्थों में स्वच्छता एक जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है।

इस यात्रा में स्वच्छ भारत मिशन केवल आदत में बदलाव से लेकर व्यवहारगत परिवर्तन तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि नागरिकों के जीवन को स्वस्थ बनाने और सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ मानसिकता में परिवर्तन लाकर बिजली उत्पादन, स्टार्टअप, कचरे से कंचन बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला कदम सिद्ध हुआ है।

जनभागीदारी से स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण

जनभागीदारी से 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल

12.50 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण

5.54 लाख से अधिक गांवों को मिला ओडीएफ प्लस का दर्जा

60 से 70 हजार प्रति वर्ष नवजात शिशुओं की जान बचाने में मिली मदद

परिवारों को चिकित्सा लागत में 8 हजार रुपये से अधिक की वार्षिक बचत

- बीमार कम पड़ने से सालाना 24,646 रुपये के बराबर समय की बचत
- कम मृत्यु दर के कारण 17,622 रुपये की बचत हुई
- शौचालय निर्माण के कारण संपत्ति के मूल्य में औसतन 19 हजार रुपये प्रति परिवार बढ़ा

93% महिलाओं को शौच के वक्त जानवरों या अन्य खतरे या किसी तरह के संक्रमण का कोई डर नहीं

5.2% GDP की जीडीपी बचत हुई हर साल

2014-19 के बीच

3 लाख डायरिया से होने वाली मौतें रोकी गईं

प्रभाव-1

जीवनशैली का अंग बनी स्वच्छता

भारत की आजादी के 7 दशक बाद जब दुनिया में महिलाएं अंतरिक्ष पर जाने के साथ हर क्षेत्र में तरक्की की नई गाथाएं लिख रही थीं, भारत की करीब 60 फीसदी आबादी के पास शौचालय की सुविधा भी नहीं थी। यह विडंबना ही थी कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल शौचालय को भारत के गांवों में तब तक एक 'लग्जरी' के रूप में माना जाता था और महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थीं। कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता है? इसलिए पीएम मोदी ने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है, वैसे नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय और मानवीय चुनौती समझकर इसके समाधान का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का ही परिणाम है कि आज देश में 100 फीसदी स्वच्छता कवरेज हासिल हुआ है। 11 वर्षों में ही लगभग 12.50 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण इस बात का प्रमाण है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान से स्वच्छ भारत मिशन एक जनआंदोलन के रूप में सफल हुआ है। जर्मन वर्ल्ड डेवलपमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक 2015 में देश के 59 फीसदी ग्रामीण और 12 फीसदी शहरी घरों में शौचालय नहीं थे। साथ ही, 52.2 करोड़ लोग खुले में शौच कर रहे थे। स्वच्छता का महत्व बढ़ने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है।

दरअसल, किसी भी नीति या योजना की सफलता का आकलन उसके प्रभावों से होता है। यह प्रभाव स्वाभाविक परिणाम मिलने से लेकर नई दिशा दिखाने वाले भी होते हैं। पहले क्रम का प्रभाव- स्वाभाविक परिणाम या लक्ष्य की पूर्ति भर होता है। दूसरे क्रम का प्रभाव- यह जीवन स्तर में बदलाव लाने वाला होता है और तीसरे

प्रभाव-2

गरिमामय और स्वस्थ जीवन का आधार

स्वच्छ भारत मिशन आज गरीबों के लिए गरिमामय जीवन का प्रतीक बन गया है। पीएम मोदी ने बीते वर्ष एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक रिपोर्ट साझा की थी, जिसमें बताया गया था कि देश में शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करने में इस मिशन जैसे प्रयासों ने कितना प्रभाव डाला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, "स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रयासों के प्रभाव को रेखांकित करने वाले शोध को देखकर प्रसन्नता हुई। उपयुक्त शौचालयों की सुलभता शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छ एवं सुरक्षित साफ-सफाई सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक गेम-चेंजर बन गई है। मुझे खुशी है कि भारत ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है।" बीते वर्ष एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय जरनल का अध्ययन आया था। इस अध्ययन को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन, यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। इसमें सामने आया कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं, जिनकी डायरिया के कारण मृत्यु हो जाती थी। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि घर में शौचालय बनने के कारण अब 90% से ज्यादा महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं को संक्रमण से होनी वाली बीमारियों में भी स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बहुत कमी आई है। लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनने से ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यूनिसेफ की एक और स्टडी है। इसके मुताबिक साफ-सफाई के कारण गांव के परिवार के हर साल औसतन 50 हजार रुपये बच रहे हैं।

प्रभाव-3

कचरे से कंचन का मंत्र खुशहाली का नया मार्ग

स्वच्छता के जज्बे को 2019 में मंजिल तो मिली। शहरों में लक्ष्य से ज्यादा शौचालय बनवाए, ग्रामीण भारत में खुले में शौच से मुक्ति के बाद प्लस रेटिंग की दौड़ शुरू हो गई लेकिन, यह एक पड़ाव भर था। इसके बाद स्वच्छता मिशन 2.0 शुरू हुआ। इसके जरिए अब कचरा और पानी के प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का जोर गंदे पानी के शोधन/प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, शहरी निर्माण से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन पर है। इसी का परिणाम है कि आज कचरे से कंचन बनाने की दिशा में नए-नए प्रयोग सामने आ रहे हैं यानी स्वच्छता का मिशन केवल शौचालय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपन्नता का नया मार्ग दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन हो रहा है। लोगों को नौकरियां मिली है। गांवों में राजमिस्त्री, प्लंबर, श्रमिकों को नए अवसर मिले हैं। यूनिसेफ का अनुमान है कि करीब-करीब सवा करोड़ लोगों को इस मिशन की वजह से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ हुआ और काम मिला है। अब क्लीन टेक से और बेहतर नौकरियां, बेहतर अवसर युवाओं को मिलने लगे हैं। वेस्ट टू वेल्थ में हो, वेस्ट के क्लेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हो, पानी के रीयूज और रीसाइकलिंग में हों...ऐसे अनेक अवसर वॉटर एंड सेनीटेशन के सेक्टर में बन रहे हैं। एक अनुमान है कि इस दशक के अंत तक इस सेक्टर में 65 लाख नई नौकरियां सृजित होंगी। घर से निकले कचरे से आज, खाद, बायो गैस, बिजली और रोड पर बिछाने के लिए चारकोल जैसे सामान बन रहे हैं। मिशन की सफलता के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सितंबर 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से भी नवाजा था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि आज पूरी दुनिया स्वच्छता अभियान के भारत के मॉडल से सीखना और अपनाना चाहती है।

क्रम का प्रभाव- बहुत दूरगामी और गहरा प्रभाव डालने वाला होता है, जिसमें समय लगता है। स्वच्छ भारत मिशन केवल प्रथम स्तर के प्रभाव यानी स्वाभाविक परिणाम तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि द्वितीय और तृतीय स्तर के प्रभावों के साथ देश को नया मार्ग भी दिखाया है।

निश्चित रूप से भारत आज स्वच्छता के मंत्र के साथ समृद्धि की ओर बढ़ रहा है क्योंकि इस अभियान ने संपन्नता के नए-नए मार्ग खोल दिए हैं। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन को भारत की आधुनिक क्रांति कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ■

बिहार, झारखंड, प. बंगाल को कनेक्टिविटी में विस्तार की सौगात

महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजबूत कनेक्टिविटी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि विकसित राष्ट्र के रास्ते पर आगे बढ़ते भारत ने बीते 11 साल में इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया है। देश के हर हिस्से तक आधुनिक कनेक्टिविटी पहुंचाने की कड़ी में ताजा उदाहरण बने हैं बिहार, झारखंड और प. बंगाल, जहां भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण व मोकामा-मुंगेर 4 लेन ग्रीनफील्ड सेक्शन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। इससे यात्रा का समय तो बचेगा ही, रोजगार-कारोबार के अवसर भी होंगे तैयार...

निर्णय : आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 3,169 करोड़ रुपये लागत वाली भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट एकल रेलवे लाइन खंड (177 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी दी।

प्रभाव : बिहार, झारखंड और प. बंगाल के बीच कनेक्टिविटी को विस्तार देने वाली यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से 'आत्मनिर्भर' बनाएगी। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बनाई गई इस परियोजना के जरिए भारतीय रेलवे के इन सबसे व्यस्ततम खंडों पर भीड़भाड़ कम होने के साथ आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास संभव हो सकेगा। इससे भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

- तीनों राज्यों के 5 जिलों को कवर करने वाली इस परियोजना से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 177 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
- यह परियोजना खंड, देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम), तारापीठ (शक्ति पीठ) जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करता है।
- मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 441 गांवों और 28.72 लाख आबादी तथा 3 आकांक्षी जिलों (बांका, गोड्डा और दुमका) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
- कोयला, सीमेंट, उर्वरक, ईंट और पत्थर आदि जैसी वस्तुओं की ढुलाई के लिए यह एक आवश्यक मार्ग है। क्षमता बढ़ने से प्रति वर्ष 1.5 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढुलाई होगी।

निर्णय : बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल मोकामा-मुंगेर खंड के हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर निर्माण को मंजूरी।

प्रभाव : करीब 4,447.38 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना की कुल लंबाई 82.40 किलोमीटर है। यह खंड मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर और मुंगेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इससे यात्रा में लगने वाला समय लगभग 1.5 घंटे तक कम हो जाएगा। साथ ही, यात्री और मालवाहक वाहनों के लिए सुरक्षित, तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी।

- 82.40 किलोमीटर की प्रस्तावित परियोजना से लगभग 14.83 लाख मानव-दिवस प्रत्यक्ष रोजगार और 18.46 लाख मानव-दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा।
- प्रस्तावित गलियारे के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यह परियोजना अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।

पूर्वी बिहार में मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर क्षेत्र आयुध कारखाने, लोकोमोटिव वर्कशॉप, खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित रसद एवं भंडारण केंद्रों के बल पर एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। भागलपुरी सिल्क की प्रमुखता के बीच भागलपुर वस्त्र व रसद केंद्र तो वहीं बड़हिया खाद्य पैकेजिंग, प्रसंस्करण और कृषि-गोदाम के लिए एक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों से भविष्य में मोकामा-मुंगेर खंड पर माल ढुलाई और यातायात का विस्तार होने की उम्मीद है।

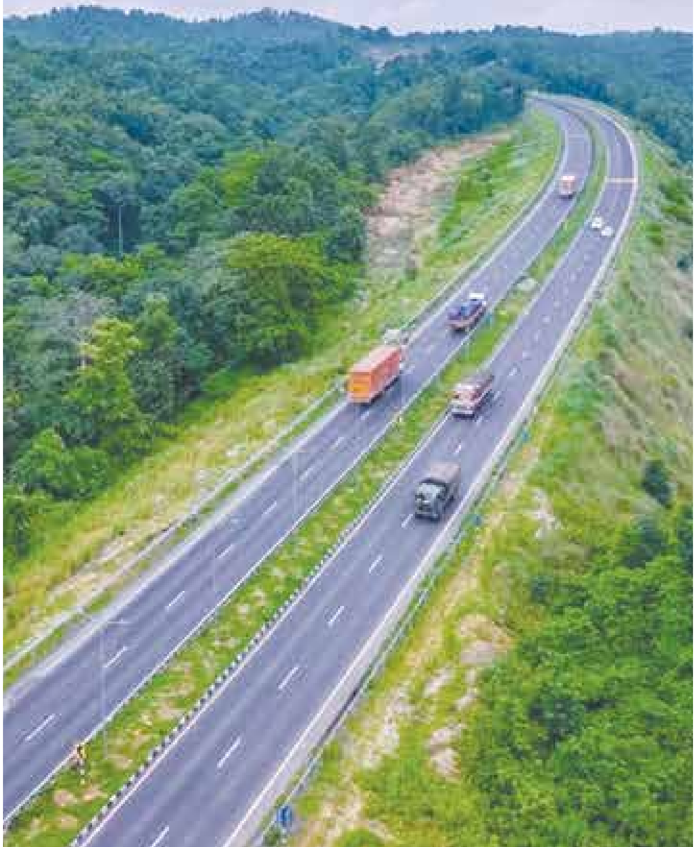

"आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन के अनुरूप हम देशभर में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसी दिशा में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। इससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों का जीवन बहुत आसान होने वाला है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

निर्णय : देश में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी।

प्रभाव : योजना वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगी। यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है।

- इस योजना का उद्देश्य देश में ई-कचरे, लिथियम-ऑयन बैटरी के कबाड़ और पुराने वाहनों के कैटेलिटिक कन्वर्टर जैसे स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को अलग करने और उत्पादन की पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करना है।
- बड़े उद्यमों के लिए कुल 50 करोड़ रुपये और छोटे उद्यमों के लिए 25 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की सीमा तय की गई है।
- इस योजना से लगभग 8,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और लगभग 70 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

जापान से एससीओ तक...

भारत पर भरोसे को नया विस्तार

आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति के चुनौती भरे दौरे में भारत न सिर्फ वैश्विक कूटनीति के केंद्र में है, बल्कि अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित भी कर रहा है। भारत पर भरोसे की यही झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 अगस्त से 1 सितंबर तक 4 दिवसीय विदेश दौरे पर भी दिखाई दी, जहां जापान ने भारत में इतिहास के सबसे बड़े निवेश की घोषणा की। वहीं चीन के तियानजिन में एससीओ के मंच से पीएम मोदी के संबोधन को न सिर्फ सराहा गया, बल्कि पहलगाम हमले जैसी कायराना आतंकी करतूत को बेनकाब करने के आह्वान वाले भारत के प्रयास को घोषणा पत्र में जगह भी मिली। वैश्विक जनसंख्या के 40% से ज्यादा और सकल घरेलू उत्पाद के 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों के संगठन एससीओ के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने न सिर्फ दुनिया का ध्यान खींचा, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दी और मजबूती...

> कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। इससे देश में विकास के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं।
>
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

तियानजिन के मंच से सुरक्षा, शांति और स्थिरता का संदेश

करीब 7 साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से सामने रखा। एससीओ के मंच से पीएम मोदी ने सुरक्षा, शांति और स्थिरता का संदेश देते हुए कहा कि इनके बिना विकास और समृद्धि संभव नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एससीओ के लिए भारत की दृष्टि और नीति तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है, जिनमें एस- सिक्योरिटी, सी- कनेक्टिविटी और ओ- ऑपर्च्युनिटी शामिल हैं।

आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में मिला एससीओ का साथ

एससीओ पर भारत के दृष्टिकोण को विस्तार देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिक्योरिटी यानी सुरक्षा पहला स्तंभ है। आतंकवाद और अलगाववाद जैसे बड़े खतरे प्रगति और विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा डालते हैं। आतंकवाद न केवल अलग-अलग देशों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह

विश्वास-विकास

हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान

विकास को बढ़ावा देने और विश्वास निर्माण में कनेक्टिविटी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भारत के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए।

सुझाव दिया

सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम

एससीओ पर अपने दृष्टिकोण के तीसरे स्तंभ ऑपर्च्युनिटी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान यह प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे सामान्य मानव तक लेकर जाएं। लोगों के बीच आपसी संपर्क के इस अवसर यानी ऑपर्च्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं।

पूरे मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती है। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ भारत की मुहिम को मिले समर्थन पर सभी को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हमने आतंकवाद का बहुत घिनौना रूप देखा। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। आतंकवाद को लेकर दोहरे रवैये पर सीधा प्रश्न खड़ा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है?

असर: पीएम मोदी के संबोधन के बाद एससीओ के तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। यह भी कहा गया कि ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों और मदद करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। घोषणापत्र में आतंकवाद-रोधी प्रयासों में दोहरे मानदंडों को खारिज किया गया और आतंकवादियों की सीमा-पार गतिविधियों को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग के महत्व पर बल दिया गया।

महत्व: जून में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा को शामिल न करने पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर हस्ताक्षर से इंकार कर दिया था। भारत के विरोध के बाद तब घोषणा पत्र जारी ही नहीं हो सका था। इसके विपरीत तियाजिन घोषणा पत्र भारत की कूटनीतिक

चीन और रूस के साथ द्विपक्षीय बैठक

बहुध्रुवीय विश्व में अब भारत भी साझेदार

तियानजिन में एससीओ की बैठक से इतर 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और 1 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। समिट और समिट से अलग औपचारिक और अनौपचारिक बात और मुलाकात में तीनों देशों के नेताओं की तस्वीरों ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी के साथ बातचीत में कहा कि भारत-चीन सहयोग दोनों देशों की 280 करोड़ की आबादी के हित में हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार, दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और चीन एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार हैं। एशिया और दुनिया में बहुध्रुवीय समीकरणों में भारत-चीन का सहयोग जरूरी है। दोनों नेताओं के बीच कई अन्य मुद्दों पर भी बात हुई।

इन पहलों का स्वागत

- पीएम मोदी ने सीमा पर शांति बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया।
- दोनों नेताओं ने सीमा पर विवाद के बाद पिछले वर्ष हुए डिस-एंगेजमेंट की सराहना की।
- न्यायपूर्ण व स्वीकार्य समाधान पर जोर दिया।
- विशेष प्रतिनिधियों के प्रयासों का स्वागत।

इन पहलों पर जोर

- भारत और चीन के बीच जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो सकती हैं।
- आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए वीजा सिस्टम में सुधार किया जाएगा।
- कैलाश-मानसरोवर यात्रा फिर शुरू ।

इन मुद्दों पर बनी सहमति

पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच विश्व व्यापार को स्थिर करने में दोनों देशों की साझी भूमिका पर सहमति बनी। व्यापार घाटे को कम करने और पारदर्शी नीतियों के जरिए संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। रणनीतिक दृष्टि से व्यापार व निवेश को और बढ़ाने के लिए दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई।

राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी कार में वार्ता के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बैठक की। बैठक स्थल के लिए राष्ट्रपति पुतिन खुद अपनी कार से उन्हें लेकर पहुंचे। इससे जुड़ी तस्वीर पीएम मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में कार में एक साथ 45 मिनट की यात्रा और बातचीत छाई रही। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं।

यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थाई शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को निमंत्रण देते हुए कहा कि इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। उधर, रूस की ओर से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध समाप्ति के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

सफलता का बड़ा दस्तावेज है। जापान से चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन और इस दौरान हुई मुलाकातों के साथ बहुध्रुवीय विश्व में भारत एक बेहतर और मजबूत भूमिका की ओर बढ़ा है। राजनीतिक उथल-पुथल और युद्ध के दौर के बीच इन यात्राओं में भारत पर दोस्तों के बढ़ते भरोसे को नया विस्तार भी दिया है। ■

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

भारत और मॉरीशस...

साझेदारी से बढ़कर अब एक परिवार

भारत-मॉरीशस के बीच संबंध केवल राजनीति नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सभ्यतागत कड़ियों से जुड़े हैं। संबंधों की यही आत्मीयता मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के वाराणसी दौरे पर भी दिखाई दी। अपने संसदीय क्षेत्र और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में विख्यात काशी की धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनन्य मित्र का स्वागत करते हुए मॉरीशस को साझेदारी से कहीं आगे बढ़कर बताया परिवार...

बहुध्रुवीय विश्व में लगातार बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भी भारत और मॉरीशस के रिश्ते आत्मीय मित्र के रहे हैं। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'विजन महासागर' में मॉरीशस का अहम स्थान है। रिश्तों की यह गर्माहट 11 सितंबर को काशी में भी दिखाई। परंपरा से हटकर नई दिल्ली की बजाय काशी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह केवल औपचारिक नहीं, बल्कि एक आत्मिक मिलन है। मॉरीशस के विकास में भारत की साझेदारी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के बाहर पहला जनऔषधि केंद्र अब मॉरीशस में स्थापित हो चुका है। इसके साथ ही भारत अब मॉरीशस में 500 बेड के शिवसागर रामगुलाम आयुष अस्पताल और वेटरनरी व एनिमल हॉस्पिटल में भी सहयोग देगा। पीएम मोदी ने मॉरीशस की प्राथमिकताओं को देखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की। यह पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा। दोनों देशों के बीच 7 एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए।

भारत-जापान आर्थिक साझेदारी का नया अध्याय

10 साल में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा जापान

भारत और जापान के रिश्ते कुछ वर्ष या दशक नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ 1400 वर्ष से ज्यादा पुरानी ऐतिहासिक नींव पर खड़े हैं। इसके मूल में आध्यात्मिक आत्मीयता और सुदृढ़ सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंध निहित रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने इन ऐतिहासिक संबंधों को एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में बदल दिया। अब 30-31 अगस्त को उनकी जापान यात्रा ने इस आत्मीयता में जोड़ा आर्थिक और भविष्य की साझेदारी का नया अध्याय...

आज विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में भारत और जापान की साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उगते सूरज के इस देश के भारत में बढ़ते भरोसे और आपसी साझेदारी को जापान बैंक ऑफ इंटरनेशल कोऑपरेशन (JBIC) और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (JETRO) के कथनों से भी समझा जा सकता है। JBIC जहां भारत को प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन मानता है तो JETRO बताता है कि 80 प्रतिशत कंपनियां भारत में विस्तार करना चाहती हैं और इनमें से 75 प्रतिशत कंपनी मुनाफे में हैं। इसी भरोसे के साथ जापानी कंपनियों ने भारत में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। इसमें से 13 बिलियन डॉलर का निवेश तो केवल पिछले 2 वर्षों में ही आया है।

भारत पर बढ़ते इसी विश्वास का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन भारत-जापान इकॉनोमिक फोरम को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप तक हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। पीएम मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ पिछले 11 वर्षों में भारत परिवर्तनगाथा का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि भारत

भारत-जापान साझेदारी
10 साल का रोडमैप तैयार

दोनों देशों के बीच 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक दशक का रोडमैप तैयार हुआ। इस रोडमैप का सबसे अहम हिस्सा है- 'इंडिया-जापान ज्वाइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड'... इसमें आर्थिक विकास से लेकर सुरक्षा, तकनीक, नवाचार, स्वास्थ्य, सतत विकास, मोबिलिटी और आपसी आदान-प्रदान तक कई अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया। इस रोडमैप के तहत निवेश, नवाचार, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लोगों के बीच संपर्क और अत्याधुनिक भागीदारी के क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। जापान की ओर से भारत में इतिहास के सबसे बड़े निवेश पर बनी सहमति के बाद अगले 10 वर्ष में जापान से भारत में 100 खरब येन निवेश का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देश लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप उद्यमों पर भी विशेष ध्यान देंगे।

- जापान ने निवेश के अलावा सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग का प्रस्ताव भी रखा है। यह ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों टिकी हुई हैं।
- दोनों देशों ने विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आठ सूत्रीय महत्वाकांक्षाओं और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। दोनों नेताओं की ओर से जारी साझा आर्थिक और सुरक्षा दृष्टिपत्र में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने का वादा किया गया।
- भारत और जापान अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। दोनों देश रक्षा तकनीक साझा करेंगे और हथियारों के उत्पादन की साझा संभावनाओं पर काम करेंगे।

में आज राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता है। पॉलिसी में पारदर्शिता है। आज भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जो जल्द दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। व्यापार के लिए अब सिंगल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की है। पीएम मोदी ने कहा कि इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है। हमारा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और स्ट्रैटजी है। दुनिया ने इन्हें पहचाना ही नहीं, बल्कि सराहा भी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-जापान साझेदारी के 5 स्तरों का जिक्र कर कुछ सुझाव भी दिए। भारत में जापानी कंपनियों सुजुकी और डाइकिन को मिली सफलता पर के बारे में उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है। हम साथ मिलकर बैटरी, रोबाटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप-बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी इसे दोहरा सकते हैं। पीए मोदी ने जापान के लोगों से भारत आकर 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के विजन के साथ काम करने का आह्वान किया। जापान को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के रूप में टेक पावरहाउस बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत टैलेंट पावरहाउस है। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर 21वीं सदी में टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी और नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत-जापान

प्राइवेट सेक्टर्स के साथ 150 से अधिक एमओयू

भारत-जापान बिजनेस फोरम के तहत प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों के साथ कई समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार इस दौरान 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 150 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

- दोनों देशों के समाज को जोड़ने के लिए दीर्घकाल में रणनीतिक रिश्तों की मजबूत नींव रखते हुए जापान ने भारत के साथ मानव संसाधन सहयोग को भी प्राथमिकता दी है। आने वाले 5 वर्षों में 5 लाख भारतीयों और जापानियों के बीच शैक्षणिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक आदान-प्रदान का लक्ष्य रखा है। 50 हजार स्किल्ड प्रोफेशनल भारत से जापान भेजे जाएंगे।
- भारत की इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी **JAXA** मिलकर चंद्रयान-5 मिशन पर काम करेंगे। दोनों देश चांद के ध्रुवीय इलाकों की खोज के लिए एक साथ मिशन चलाएंगे। समझौते के मुताबिक, **JAXA** अपने **H**3-24**L** रॉकेट से इस मिशन को लॉन्च करेगा। यह रॉकेट इसरो के चंद्र लैंडर को लेकर जाएगा। इस लैंडर के अंदर जापान द्वारा निर्मित चंद्र रोवर होगा।
- भारत का सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट और जापान का विदेश मंत्रालय आपसी प्रशिक्षण में साथ देंगे। साथ ही दोनों देशों के वैज्ञानिक और स्टार्टअप भी रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मिलकर काम करेंगे।
- दोनों देशों के बीच बायोगैस और बायोफ्यूल जैसे टिकाऊ ईंधन पर भी रिसर्च और साझेदारी होगी। जापान के कंसाई और क्यूशू क्षेत्रों में नए व्यापार मंच बनाए जाएंगे ताकि व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते गहरे हों।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए **QR** कोड स्कैन करें।

साझेदारी का जिक्र कर पीएम मोदी ने कहा कि जापान की उत्कृष्टता और भारत का पैमाना एक आदर्श साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं। पीएम मोदी ने स्किल डेवलपमेंट पर दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर कुशल कार्यबल तैयार करने का भी सुझाव दिया। एक अनोखी पहल के तहत जापान के 16 प्रीफेक्चर्स (जो भारत में मुख्यमंत्रियों के समकक्ष हैं) के गवर्नरों ने टोक्यो आकर पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन पीएम इशिबा के साथ मियागी प्रांत के सेंडाई में स्थित एक सेमीकंडक्टर संयंत्र का दौरा करने के लिए शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से यात्रा की। पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान में ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सेंडाई में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी जापानी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड (टीईएल मियागी) का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में टीईएल की भूमिका, इसकी उन्नत विनिर्माण क्षमताओं और भारत के साथ इसके जारी एवं नियोजित सहयोग के बारे में जानकारी दी गई। संयंत्र के दौरे से नेताओं को सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, निर्माण और परीक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच मौजूद अवसरों की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई। ■

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए **QR** कोड स्कैन करें।

सेमीकंडक्टर
आधुनिक तकनीक की धड़कन

आज के डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर तकनीक राष्ट्रीय विकास एवं सामरिक स्वावलंबन की कुंजी बन चुकी है। यही वजह है कि आर्थिक वृद्धि और तकनीकी सशक्तीकरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत सरकार ने कई मजबूत पहलें की हैं जिनकी वजह से भारत, तकनीकी मानचित्र पर दुनिया का विश्वसनीय साझेदार बनने की ओर अग्रसर है। भारत आने वाले समय में तकनीक का निर्माता बनेगा इसकी बानगी दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमीकॉन इंडिया-2025 में भी दिखी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव की रखेगी आधारशिला...

> वो दिन दूर नहीं, जब भारत की सबसे छोटी चिप, दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी।
>
> - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नवाचार का नया नाम है भारत, तकनीक का नया ताज है भारत और इस यात्रा के पथप्रदर्शक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल सेमीकंडक्टर सिर्फ एक चिप नहीं है बल्कि आधुनिक सभ्यता की धड़कन और जीवनरेखा है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है तो यह संकल्प भी है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की हर डिवाइस में मेड इन इंडिया चिप हो। दो से चार सितंबर तक आयोजित सेमीकॉन इंडिया-2025 के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि 'तेल काला सोना' था लेकिन 'चिप डिजिटल हीरा' है। तेल ने पिछली सदी को आकार दिया वहीं 21वीं सदी की शक्ति अब छोटी चिप पर केंद्रित है।

सेमीकंडक्टर का बढ़ता बाजार

110 बिलियन डॉलर का होगा भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2030 तक।

1 ट्रिलियन डॉलर का होगा सेमीकंडक्टर का वैश्विक बाजार वर्ष 2030 तक।

20% सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाले विश्व के इंजीनियर भारत से हैं।

10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को अभी तक अनुमति मिली है जिसमें कुल ₹1.6 लाख करोड़ का निवेश किया गया है।

- सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करने वाले 23 स्टार्टअप को मान्यता देकर वित्तीय मदद की जा रही है।
- स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत कुल 85 हजार छात्रों को ट्रेनिंग दी जानी हैं जिसमें 60 हजार को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वच्छ ऊर्जा, क्वांटम और अग्रणी क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर क्रांति लाने के लिए 1 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता के साथ डीप टेक अलायंस की घोषणा की।

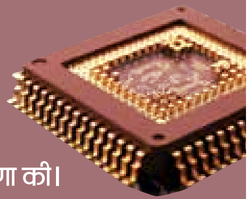

ये है भारत की स्पीड... दुनिया का बढ़ता भरोसा

भारत की स्पीड का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि साल 2021 में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरु किया और साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया। साल 2024 में कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए, साल 2025 में 5 और प्रोजेक्ट्स क्लीयर किए। अब कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट में 18 अरब डॉलर यानी डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। सेमीकंडक्टर में स्पीड मैटर करती है। फाइल से फैक्ट्री का समय जितना कम होगा, जितना कम पेपरवर्क होगा, वेफर वर्क उतना जल्द शुरू हो पाएगा। इसी अप्रोच के साथ सरकार काम कर रही है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से केंद्र और राज्यों के सारे अप्रूवल एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं।

सेमीकॉन इंडिया-2025

सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के साथ तकनीक और सेंटर बनाने के लिए कुल 12 समझौते हुए।

आकार में छोटा होने के बावजूद ये चिप वैश्विक प्रगति को तेजी से बढ़ाने की क्षमता रखती है। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर का बाजार पहले ही 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। आने वाले वर्षों में इसके एक ट्रिलियन डॉलर पार करने की उम्मीद है।

तकनीक की महत्ता को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस क्षेत्र में विशेष रूचि रखते हैं जिसके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। देश भर में प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के तहत सेमीकंडक्टर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। भारत बैकएंड ऑपरेशन से आगे बढ़कर एक पूर्ण-स्टेक सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में भले ही हमारी यात्रा देर से शुरू हुई है लेकिन अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। इस वर्ष से वाणिज्यिक चिप का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की तेज प्रगति को दर्शाता है।

सेमीकंडक्टर सफलता की गाथा किसी एक कार्यक्षेत्र या किसी एक तकनीक तक सीमित नहीं है। भारत एक व्यापक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है- जिसमें डिजाइनिंग, निर्माण, पैकेजिंग और उच्च तकनीक वाले उपकरण सभी शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन केवल एक फैब स्थापित करने या एक चिप बनाने तक सीमित नहीं है। भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में विश्व में सबसे उन्नत तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहा है। नोएडा और बेंगलुरु में विकसित किए जा रहे डिजाइन केंद्र दुनिया के सबसे उन्नत चिप पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम कर रहे या भविष्य तलाश रहे युवा उद्यमियों और स्टार्टअप को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ■

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

परमाणु ऊर्जा क्षमता होगी अगले छह वर्ष में तीन गुनी

असैन्य परमाणु ऊर्जा देश के भावी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगी। यही वजह है कि वैश्विक चुनौतियों और देश में तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा को भविष्य की एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में चिन्हित किया है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता में वर्ष 2031-32 तक तीन गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा है ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी किया जा सके हासिल...

भारत सरकार परमाणु ऊर्जा की जिस क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उससे न सिर्फ ऊर्जा की बढ़ती मांग पूरी होगी बल्कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी घटेगी। यही नहीं स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में भारत के वैश्विक वादों को भी इससे मजबूत आधार मिलेगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि परमाणु ऊर्जा के विस्तार से देश की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास होगा। भारत सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास से वर्ष 2031-2032 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता जो वर्तमान में 8,880 मेगावाट है बढ़कर 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने की उम्मीद है।

परमाणु ऊर्जा विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह के अनुसार पिछले 10 साल के दौरान भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013-14 में परमाणु ऊर्जा की क्षमता जहां 4,780 मेगावाट थी वह बढ़कर 2023-24 में 8,180 मेगावाट तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से वार्षिक विद्युत उत्पादन भी 2013-14 के 34,228 मिलियन यूनिट से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 47,971 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया है। देश में वर्तमान में 25 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,880 मेगावाट है। संसद में एक लिखित जवाब में बताया

> "रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है, समय अनुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म्स करते जाना होता है, हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर आए हैं। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा के द्वार खोल दिए हैं, हम शक्ति को जोड़ना चाहते हैं।"
>
> -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

स्वदेशी रूप से डिजाइन किए जा रहे हैं रिएक्टर

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) द्वारा प्रदर्शन के लिए तीन प्रकार के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। ये रिएक्टर हैं...

- 200 मेगावाट भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर।
- 55 मेगावाट लघु मॉड्यूलर रिएक्टर।
- हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त थर्मोकेमिकल प्रक्रिया के साथ युग्मन द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 5 मेगावाट उच्च तापमान गैस कूल्ड रिएक्टर।
- इन रिएक्टरों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद इन रिएक्टरों का निर्माण 60 से 72 महीने में पूरा होने की संभावना है।

तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

भारत अपने सीमित यूरेनियम संसाधनों के अच्छे उपयोग और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा एवं विशाल थोरियम संसाधनों का दोहन करने के लिए तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चला रहा है।

परमाणु ऊर्जा क्षमता का होता विस्तार

- पिछले 10 साल में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है।
- वर्तमान में देश में उत्पादित कुल बिजली में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 3 प्रतिशत है।
- वर्ष 2024-25 में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से 56,681 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ।

15,300 मेगावाट क्षमता के 21 नए परमाणु रिएक्टर पर काम जारी।

गया है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा कुल 15,300 मेगावाट क्षमता के 21 परमाणु रिएक्टर क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। यही नहीं, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सहित कुल 7,300 मेगावाट क्षमता के नौ और रिएक्टर भी निर्माणाधीन हैं।

केंद्र सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन की भी शुरुआत की है, जो लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। इस पहल के लिए 20 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से डिजाइन और परिचालन एसएमआर विकसित करना है। परमाणु ऊर्जा मिशन में ग्रीन फील्ड्स, ब्राउन फील्ड्स, कैप्टिव संयंत्रों के रूप में तथा दूरस्थ स्थानों पर ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए बड़े तथा छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने की तैयारी की जा रही है। परमाणु ऊर्जा मिशन जैसी पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी करना, लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों का अनुसंधान एवं विकास और नई उन्नत तकनीकों के लिए सक्षम उपाय करना है। ■

पूर्वोत्तर | विकसित भारत का संकल्प सारथी

पूर्वोत्तर अब भारत के विकास मानचित्र की परिधि में नहीं, बल्कि मजबूती के साथ विकास के केंद्र बिंदु में है। वर्ष 2014 के बाद यह क्षेत्र विकसित राष्ट्र के संकल्प पथ पर भारत के विकास का सारथी बना हुआ है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक्ट ईस्ट' के विजन के साथ दूरदर्शी नीति निर्माण, रिकॉर्ड निवेश और विशेष मंत्रालय एवं समन्वित प्रयासों को जाता है। पूर्वोत्तर को लेकर पीएम मोदी की संवेदनशीलता की यही झलक 13-14 सितंबर को उनके दो दिवसीय दौरे पर भी दिखाई दी, जहां मिजोरम, मणिपुर और असम को उन्होंने दी 36 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सौगातें...

आजादी के बाद देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के बड़े शहरों में विकास हुआ, वहां सपने पले, नौजवानों को नए मौके मिले। अब 21वीं सदी का यह समय पूर्व और पूर्वोत्तर का है, जहां सिर्फ सपने ही साकार नहीं हो रहे, बल्कि भारत के विकास की मुख्यधारा से जोड़ प्रगति के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। 11 सालों में 10 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 16 हजार किमी से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर मिजोरम में पहली बार रेल लाइन तक पूर्वोत्तर एक नई परिवर्तन गाथा से गुजर रहा है। नए भारत के साथ आगे बढ़ते पूर्वोत्तर की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी दिखाई दी। मणिपुर के चुराचांदपुर में

मणिपुर : भारत के मुकुट पर सजा रत्न

मणिपुर के विकास के लिए पीएम मोदी ने चुराचांदपुर में 7,300 और राजधानी इंफाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर रेल और आईटी क्षेत्र के भी कार्य शामिल हैं।

- आधारशिला : 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से मणिपुर में शहरी सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना।
- 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना।
- राज्य में 9 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराना शामिल है।
- उद्घाटन : 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से इंफाल के मंत्रीपुखरी में सिविल सचिवालय के साथ-साथ आईटी एसईजेड भवन और नया पुलिस मुख्यालय।
- दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन और चार जिलों में महिलाओं के लिए अनूठा इमा मार्केट।

इन परियोजनाओं की शुरुआत से राज्य के विकास ने पकड़ी है रफ्तार...

- 3,700 करोड़ रुपये पिछले कुछ वर्षों में इन क्षेत्रों में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च हुए हैं।
- 8,700 करोड़ रुपये की नई राजमार्ग परियोजनाओं पर भी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है।
- 2,200 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार जिरीबाम तक रेलवे लाइन जल्द ही इंफाल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी।
- 400 करोड़ रुपये की लागत से इंफाल में हवाई अड्डा।
- पीएम आवास योजना से 60 हजार से अधिक घर बन चुके हैं।
- एक लाख से अधिक परिवारों को मणिपुर में मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में लगभग 2.5 लाख मरीजों को मुफ्त इलाज मिला है।
- आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों को 350 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई।
- 7,000 नए घर बनाने में सरकार सहायता कर रही है ताकि विस्थापितों की मदद की जा सके।
- 3,000 करोड़ रु. के विशेष पैकेज की मंजूरी हाल ही में दी गई है।
- 500 करोड़ रुपये विशेष रूप से विस्थापितों की सहायता के लिए आवंटित किए गए।
- 500 से ज्यादा गांवों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है।
- राज्य में 18 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं।

विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी, भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। बॉर्डर से सटा राज्य होने के चलते मणिपुर की चुनौतियों के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसी वजह से यहां रेल और रोड, दोनों पर जोर दिया है। मणिपुर के लाखों घरों तक नल से जल पहुंचाना हो या आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बीते कुछ समय से हिंसा की चपेट में रहे राज्य के प्रभावित लोगों से हुई बातचीत का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद और विश्वास है की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। उधर, राजधानी इंफाल में करोड़ों रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह मणिपुर के उज्ज्वल भविष्य को नई ऊर्जा से भर देंगी।

मिजोरम हो, मणिपुर हो या असम अष्टलक्ष्मी का हर राज्य अब विकास को लेकर भारत की सोच और उसे क्रियान्वित करने की प्रतिबद्धता की कहानी कह रहा है। पीएम मोदी ने कहा, "किसी भी

पहली बार रेलवे के मानचित्र पर आइज़ोल

सितंबर का महीना मिजोरम वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। लंबे इंतजार के बाद आइजोल भारत के रेलवे मानचित्र पर पहुंच गया। साथ ही पीएम मोदी ने राज्य के लिए 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

- 8,070 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन।
- इस रेल लाइन में जटिल भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से 45 सुरंगें और 55 बड़े एवं 88 छोटे पुल बनाए गए हैं।
- **तीन नई एक्सप्रेस ट्रेन :** सैरांग (आइजोल)-दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग-गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग-कोलकाता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। आइजोल अब देश की राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ गया।
- त्लांगनुआम में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन।
- **शिलान्यास :** 500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आइजोल बाईपास रोड, थेनजोल-सियालसुक रोड और खानकाउन-रोंगूरा रोड परियोजना की नींव रखी गई।
- लॉन्गटलाई-सियाहा रोड पर छिमटुईपुई रिवर ब्रिज की नींव रखी।
- खेलो इंडिया बहुउद्देशीय इंडोर हॉल की नींव।
- ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आइजोल के मुआलखांग में 30 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाले एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की नींव।

असम की पहचान निरंतर हो रही मजबूत

भारत की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए असम में बायोएथेनॉल संयंत्र के साथ-साथ कुल 18,530 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया...

- **उद्घाटन :** असम के नुमालीगढ़ में, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में असम बायोएथेलॉल संयंत्र का उद्घाटन।
- बांस से एथेनॉल बनाने वाले एक नए संयंत्र का भी उद्घाटन किया।
- **शिलान्यास :** नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र।
- दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज।
- गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना, यह रिंग रोड 5 राष्ट्रीय राजमार्गों, 2 राज्य राजमार्ग, 1 हवाई अड्डा, 3 रेलवे स्टेशन और अंतर्देशीय जल टर्मिनल को जोड़ेगा। ब्रह्मपुत्र पर कुरुवा-नरेंगी पुल।
- **अन्य पहल :** मोरीगांव में 27 हजार करोड़ रुपये के निवेश से एक सेमीकंडक्टर फैक्टरी का निर्माण किया जा रहा है।
- बांस की खेती में सरकार सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये का सहयोग करेगी।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए **QR** कोड स्कैन करें।

> "मणिपुर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है... जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें...हमें हिल्स और वैली के बीच सौहार्द का एक मजबूत सेतु बनाना है।"
>
> -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

क्षेत्र में विकास के लिए शांति स्थापित करना आवश्यक है। पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में कई पुराने संघर्षों और विवादों का समाधान किया गया है।" लोगों ने शांति का मार्ग चुना है और विकास को प्राथमिकता दी है। हाल ही में पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के विभिन्न समूहों के साथ बातचीत हुई है। यह प्रयास भारत सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो शांति स्थापित करने के लिए संवाद, सम्मान और आपसी समझ पर जोर देती है। पीएम मोदी ने सभी संगठनों से शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की अपील की है। ■

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए **QR** कोड स्कैन करें।

'वात्सल्यमूर्ति' निर्णायक नेता व कुशल प्रशासक

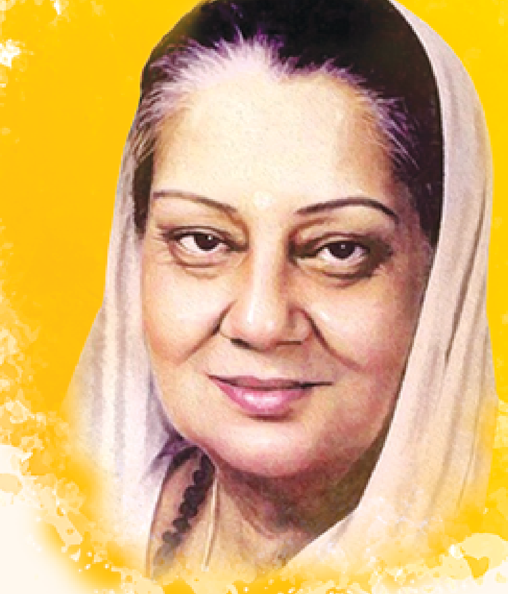

जन्म : 12 अक्टूबर 1919 ■ मृत्यु : 25 जनवरी 2001

राष्ट्रभक्ति, सरलता और मानवता की त्रिवेणी राजमाता विजयाराजे सिंधिया का संपूर्ण जीवन विचारधारा, सिद्धांत और जनसेवा के प्रति समर्पित रहा। राजसी परिवार से आने के बाद भी उन्होंने अपने आप को मानवकल्याण और राष्ट्रसेवा के लिए आहूत किया। पद और सत्ता के मोह से दूर राष्ट्रसेवक के रूप में जीवन जीकर उन्होंने राजनीति में उच्च आदर्श स्थापित किए। आपातकाल के समय लोकतंत्र पुनर्स्थापित करने के लिए अनेक यातनाएं सहीं, लेकिन निरंतर संघर्षरत रहीं। वह केवल वात्सल्यमूर्ति ही नहीं, निर्णायक नेता और कुशल प्रशासक भी थीं। राजमाता विजयाराजे उन लोगों में से एक थीं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनकल्याण और राष्ट्र सेवा को किया समर्पित...

कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा निकली हुई थी। दिसंबर और जनवरी के समय की बात रही होगी जिस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। यह यात्रा रात 12-1 बजे के करीब मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास शिवपुरी पहुंची। दिनभर की थकान रहती है ऐसे में यात्रा में शामिल लोग निवास स्थान पर जाकर नहा-धोकर सो जाते थे ताकि सुबह जल्दी तैयार हो सकें। रात के 2 बजे होंगे। यात्रा में शामिल एक व्यक्ति नहा-धोकर सोने की तैयारी कर रहा था तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। व्यक्ति ने जब दरवाजा खोला तो सामने राजमाता विजयाराजे खड़ी थीं। कड़ाके की ठंड और सामने राजमाता को देखकर वह व्यक्ति हैरान था। उन्होंने मां को प्रणाम किया और कहा कि मां आधी रात में, विजयाराजे ने कहा कि बेटा, आप ऐसा करो गर्म दूध पीकर सो जाइए। फिर वह हल्दी वाला दूध देकर चली गईं। दूसरे दिन सुबह में उस व्यक्ति को पता चला कि उस यात्रा में ड्राइवर और कार्यकर्ता सहित जितने भी 30-40 लोग शामिल थे हर एक के कमरे में जाकर उन्होंने रात के दो बजे खुद दूध का गिलास दिया। विजयाराजे ने जिस व्यक्ति को कड़ाके की सर्द रात में दो बजे जाकर दूध दिया था वो कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जीवनपर्यंत मां का प्यार क्या होता है, वात्सल्य क्या होता है, उस घटना को कभी नहीं भूल सके। यह देश का सौभाग्य है कि विजयाराजे जैसी महान विभूतियों ने देश की धरती को अपने त्याग और तपस्या से सींचा है।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कहती थीं- "मैं एक पुत्र की नहीं, मैं तो सहस्रों पुत्रों की मां हूं, उनके प्रेम में आकंठ डूबी रहती हूं।" हर देशवासी को अपना परिवार मानने वाली विजयाराजे सिंधिया ने अपना पूरा जीवन, लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। 12 अक्टूबर

1919 को जन्मीं विजयाराजे का विवाह से पहले किसी राजपरिवार से संबंध नहीं था। मध्य प्रदेश के सागर के सामान्य परिवार में जन्म लेने के साथ उन्होंने लेखा दिव्येश्वरी से ग्वालियर के सिंधिया परिवार में विवाह के बाद विजयाराजे तक का सफर ही तय नहीं किया, बल्कि सबको अपना भी बनाया। यह पाठ भी पढ़ाया कि जनसेवा के लिए, राजकीय दायित्वों के लिए किसी खास परिवार में जन्म लेना ही जरूरी नहीं होता। कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति, जिनके भीतर योग्यता है, प्रतिभा है, देश सेवा की भावना है, वह इस लोकतंत्र में सत्ता को भी सेवा का माध्यम बना सकता है। उनके पास सत्ता, संपत्ति और सामर्थ्य था, लेकिन उन सबसे बढ़कर जो उनकी अमानत थी, वो थी संस्कार, सेवा और स्नेह की सरिता। सांसद और जनसंघ की संस्थापक सदस्य रहीं राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने यह साबित किया कि जनप्रतिनिधि के लिए राजसत्ता नहीं, जनसेवा सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया और जीवन का महत्वपूर्ण कालखंड जेल में बिताया। आपातकाल के दौरान तिहाड़ जेल से उन्होंने अपनी बेटियों को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी थी। उन्होंने लिखा था- "अपनी भावी पीढ़ियों को सीना तानकर जीने की प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से हमें आज की विपदा को धैर्य के साथ झेलना चाहिए।"

आमजन के प्रति विजयाराजे सिंधिया की भावना को मथुरा के बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान की गई उनकी उस प्रार्थना से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण से यह कामना की थी-"हे कृष्ण! ऐसी बांसुरी बजाओ कि पूरे भारत के नर-नारी पुनः जागरूक हो उठें।" नारीशक्ति के बारे में तो वो विशेषतौर पर कहती थीं कि-"जो हाथ पालने को झुला सकता है, वह विश्व पर राज भी कर सकते हैं।" आध्यात्मिकता के साथ भी उनका गहरा जुड़ाव था। साधना, उपासना, भक्ति उनके अंतर्मन में रची बसी थी, लेकिन जब वो भगवान की उपासना करती थीं तो उनके पूजा मंदिर में एक चित्र भारत माता का भी होता था। अद्भुत संयोग है कि रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उनकी जन्मशताब्दी के साल में ही उनका वह सपना भी पूरा हुआ।

अपनी स्मृतियों को लेकर विजयाराजे ने अपनी लिखी एक किताब में कहा है "एक दिन ये शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा जहां से आई है, वहीं चली जाएगी शून्य से शून्य में। स्मृतियां रह जाएंगी। अपनी इन स्मृतियों को मैं उनके लिए छोड़ जाऊंगी, जिनसे मेरा सरोकार रहा है, जिनकी मैं सरोकार रही हूं।" ऐसे कई मौके आए जब पद उनके पास चल कर आए लेकिन उन्होंने उसे विनम्रता के साथ ठुकरा दिया। 25 जनवरी 2001 को उनका निधन हो गया। 12 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्मशती समारोह के उपलक्ष्य में 100 रुपये के मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। ■

> "राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण और राष्ट्रसेवा को समर्पित कर दिया। गरीबों और वंचितों के लिए प्रयास, सशक्त भारत के निर्माण में हर किसी को प्रेरित करने वाले हैं। वह साहस और दूरदर्शिता का पर्याय थीं।
>
> **-नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

Narendra Modi
@narendramodi

Our Indian Women's Hockey Team has made the nation proud by winning the Silver Medal in the Women's Asia Cup 2025. Congratulations to them. Their determination and team spirit are simply outstanding. Wishing them the very best for the times to come.

Rajnath Singh
@rajnathsingh

आईएएसवी त्रिवेणी आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। त्रिवेणी द्वारा तय की गई हर नॉटिकल मील यात्रा, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम है।

Amit Shah
@AmitShah

देश के सभी अभिभावकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों से मातृभाषा में संवाद करें। बच्चों को मातृभाषा बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाएँ।

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

Heartiest Congratulations to Shri @CPRGuv Ji on being elected as the Vice-President of India. His long-standing public service, commitment to democratic values, and vision for the nation will undoubtedly enrich the august office he now assumes, while also strengthening India's voice both within the country and on global platforms.

Nirmala Sitharam...
@nsitharamanoffc

Artificial Intelligence (AI) is not static. It is a rapidly progressing, real-time and dynamic. Therefore, all of us will have to be conscious that we don't sit back on the ethics.

We need to be clear that regulation has to run the race equally as much as the technology is running it. If the technology is on a sprint, the regulation has to be on the sprint, too.

Sarbananda Sono...
@sarbanandsonwal

भारत की नई तरक्की का इंजन, माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने उत्तर-पूर्व को केवल विकास ही नहीं दिया, बल्कि हमारी गरिमा लौटाई, हमारी आशाओं को जगाया और असीम संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

'मोदी दशक' में उत्तर-पूर्व ने पहली बार महसूस किया कि वह भारत के हृदय के केंद्र में है।

भारत कच्चे तेल, गैस के आयात को कम करने के लिए कदम उठा रहा : पीएम मोदी

कोलकाता में आज रक्षा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

असम में रखीं 6,300 करोड़ परियोजनाओं की आधारशिला

मणिपुर में पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़ी भीड़

मणिपुर के लोगों में बेहतरी की उम्मीद जगी

मैतेई बोले-हालात धीरे-धीरे संभल रहे

ऐतिहासिक : अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम, पीएम ने ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

पीएम मोदी ने कहा-पूर्वोत्तर को पहले वोट बैंक समझा जाता था, अब यह देश का विकास इंजन बन गया

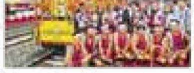

प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करना आसान हुआ : मोदी

शुभारंभ

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।

देश में करीब एक करोड़ पांडुलिपि मौजूद

भारत-मॉरीशस पार्टनर नहीं परिवार, दोनों देश स्थानीय मुद्रा में करेंगे कारोबार : मोदी

असम : भूपेन हजारिका के जयंती समारोह में पहुंचे पीएम कहा-उनका संगीत एक भारत-श्रेष्ठ भारत की पहचान

भूपेन हजारिका को नमन करते पीएम मोदी।

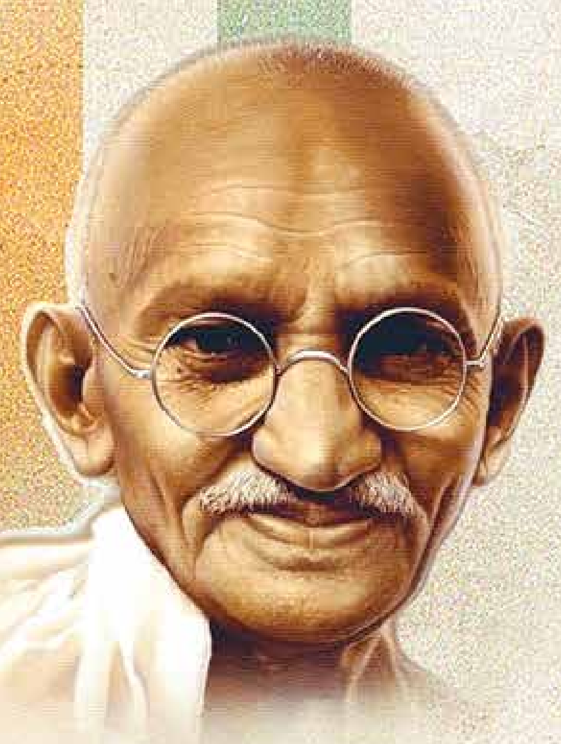

2 अक्टूबर : अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

सत्य अहिंसा और सद्भाव का विश्व को दिखाया मार्ग

उनका नाम तो मोहनदास करमचंद रखा गया था लेकिन पूरी दुनिया में वह 'महात्मा' के नाम से जाने जाते हैं। अहिंसा को अपना परम धर्म मानने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के असाधारण व्यक्तित्व व साधनापूर्ण जीवन ने विश्व को सत्य, अहिंसा और सद्भाव का मार्ग दिखाया। गुजरात की धरती पर जन्मे महात्मा गांधी का विराट जीवन एक सतत राष्ट्र यज्ञ के समान था। बापू के स्वदेशी, स्वभाषा व स्वराज के विचार चिरकाल तक देशवासियों को करते रहेंगे प्रेरित...

जन्म : 2 अक्टूबर 1869
मृत्यु : 30 जनवरी 1948

मैं गांधी जयंती के विशेष अवसर पर महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनकी कालजयी शिक्षाएं हमारा पथ आलोकित करती रहती हैं। महात्मा गांधी का प्रभाव वैश्विक है जो संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। सत्य, सद्भाव और समानता पर आधारित उनका जीवन और आदर्श देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणापुंज बना रहेगा।

– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 1-15 अक्टूबर, 2025

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर- DL (S)-1/3550/2023-25 डब्ल्यूपीपी संख्या- U (S)-98/2023-25, posting at BPC, Market Road, New Delhi - 110001 on 26-30 advance Fortnightly (प्रकाशन तिथि- 16 सितंबर 2025, कुल पृष्ठ-64)

प्रधान संपादक: धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक: कंचन प्रसाद, महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा. लि., बी-278, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020